04 - अल नीनोः भारत के भविष्य पर मंडराता संकट

05 - श्रम की मृत्यु और चेतना के पुनर्जन्म का नया समय

A Daily News Magazine
भोपाल
मंगलवार, 30 जून, 2026

06 - कौन किसके संपर्क में है ?

07 - 3 साल की जुड़वां बहनों ने रचा इतिहास

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 298, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मैं कुछ गुनगुनाऊँगी, अपनी ही लय में
तराने सजाऊँगी, अपनी ही लय में
तुम्हारे तराने सुरीले हैं लेकिन
नई धुन बनाऊँगी अपनी ही लय में
पहाड़ी के कोने में तनहा से मन को
मैं सरगम सुनाऊँगी, अपनी ही लय में
जो बैठा है अंतस में मुझसे लिपट कर
उसे भी रमाऊँगी, अपनी ही लय में
न कल का पता है, न साँसें ही निश्चित
समय को बहाऊँगी, अपनी ही लय में
गिराना-सताना मुझे तो न भाता
मैं जीवन सजाऊँगी, अपनी ही लय में
नए गीत-गज़लों-तरानों को बुनकर
मैं खुद डूब जाऊँगी, अपनी ही लय में।

- डॉ. सीमा विजयवर्गीय

प्रसंगवश

यूपी : ब्राह्मणों को साधने सपा की कोशिश कितनी सफल होगी?

डॉ. प्रांजल सिंह

क्या 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश का बदलता सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की राजनीतिक बेचैनियों को बढ़ा सकता है? यह सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस लिए जरूरी हो गया है क्योंकि 17 जून को समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित ब्राह्मण सभा ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय की आबादी लगभग 10 से 11 प्रतिशत मानी जाती है, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव उसकी जनसंख्या से कहीं अधिक रहा है।

प्रदेश का हर राजनीतिक दल यह चाहता है कि सवर्णों में, ख़ासतौर से ब्राह्मण समुदाय, उसके साथ रहे जिससे सरकार बनने में आसानी हो। इसी क्रम में, ब्राह्मण समुदाय को आकर्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी (एसपी) भगवान परशुराम को एक नए राजनीतिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रही है, और 'जय परशुराम' के नारे को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ, जनेश्वर मिश्र जिन्हें प्रदेश की राजनीति में छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है, उन्हें समाजवादी पार्टी ब्राह्मण नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। 17 जून की ब्राह्मण सभा को इसी व्यापक सामाजिक और राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

क्या समाजवादी पार्टी की इन राजनीतिक क्रियाकलापों को देखते हुए बीजेपी अपने पुराने रणनीतियों की ओर लौटेगी? बात दिसंबर 2021 की है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर यूपी के ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर मंथन हुआ। आखिर में ब्राह्मणों को मनाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का काम है हर विधानसभा में टीम बनाकर ब्राह्मणों के घर-घर जाकर उन्हें मनाया जाए।

लेकिन सवाल उस समय भी यहीं था कि योगी सरकार में 10 ब्राह्मण मंत्री और विधानसभा में पार्टी के 46 ब्राह्मण विधायक होने के बावजूद बीजेपी को अलग से ब्राह्मण कमेटी क्यों बनानी पड़ी? जबकि उस समय कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को भी मंत्री विस्तार में मंत्री बनाया गया। इससे पहले, ब्राह्मणों का चेहरा बनाकर डॉ. दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम, बृजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, राम नरेश अग्निहोत्री को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वहीं, सतीश चंद्र द्विवेदी, नीलकंठ तिवारी, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और अनिल शर्मा, आनंद स्वरूप शुक्ला और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को राज्यमंत्री बनाया गया था। इस तरह योगी सरकार में दस ब्राह्मण मंत्री थे।

प्रदेश की राजनीति में आजादी के बाद से 1989 तक यूपी को छह ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिले। पहले की सियासत ही ब्राह्मण-मुस्लिम और दलित फैक्टर पर केंद्रित थी। लेकिन, मंडल आंदोलन से पिछड़ों का उभार हुआ। पर राम मंदिर आंदोलन के बाद से ब्राह्मण फिर से महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए, वह जिसके साथ रहे, सत्ता उनके साथ रही। इसके बावजूद भी भाजपा में ठाकुर वर्चस्व का सवाल योगी सरकार को झेलना पड़ा।

2022 के विस चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 403 में से 273 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125 सीटें मिली थीं। वहीं, बीजेपी को लगभग 41 प्रतिशत और समाजवादी पार्टी को लगभग 32 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए थे। बीजेपी की यह सफलता लोगों की नाराज़गी और हिंदुत्व तथा गैर-यादव पिछड़ी जातियों और गैर-जाटव दलित समुदायों के समर्थन का मिलाजुला रूप था। जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों ने राजनीतिक तस्वीर में बदलाव के संकेत दिए। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से 33 सीटों पर सिमट गई, वाराणसी तथा अयोध्या जो बीजेपी के हिंदुत्व की पाठशाला के रूप में देखा जाता था बीजेपी वहां चुनाव हार गई। जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह बड़ी जीत थी क्योंकि समाजवादी पार्टी का सूत्र पीडीए जिसने एक नया राजनीतिक ब्लॉक तैयार किया था। यह नतीजे इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण स्थिर नहीं हैं और मतदाता नए राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

ब्राह्मण समुदाय, राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश की लगभग 100 से 125 विधानसभा सीटों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हालांकि, ब्राह्मण समुदाय को एक समान और एकरूप सामाजिक समूह के रूप में देखना उचित नहीं होगा। इनके भीतर भी कई स्तरों पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभाजन मौजूद हैं। पहला हिस्सा, उन ब्राह्मण परिवारों का है, जो राजनीतिक रूप से अत्यंत सशक्त हैं और जिनका प्रदेश की सत्ता संरचना से लंबे समय से जुड़ाव रहा है। यह वर्ग राजनीतिक दलों के साथ प्रत्यक्ष संवाद, संसाधनों तक पहुंच और सत्ता के गलियारों में अपनी निरंतर उपस्थिति बनाए रखता है। अक्सर इसी वर्ग की नाराजगी को ही ब्राह्मण समुदाय की नाराज़गी मन लिया जाता है। एसपी इन्हीं वर्गों को साधने लगी हुई है।

दूसरे हिस्से, को भी दो उपवर्गों में समझा जा सकता है। पहला वर्ग, उन ब्राह्मणों का है, जो सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों, प्रशासनिक सेवाओं और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में कार्यरत हैं। आमतौर पर, इस वर्ग का राजनीतिक झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर अपेक्षाकृत अधिक देखा गया है। लेकिन इसके भीतर भी वैचारिक विविधताएं मौजूद हैं। दूसरा उपवर्ग, उन लोगों का है, जिनका संबंध ब्राह्मण समुदाय के नाम पर गठित विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रातिनिधिक संगठनों से है। इस वर्ग की वैचारिकता के कारण भारतीय जनता पार्टी से इसका जुड़ाव रहा है। इस समुदाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने बीजेपी को ही अपना प्रमुख राजनीतिक विकल्प बनाए रखा। हालांकि, इसे स्थायी राजनीतिक निष्ठा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि बदलते सामाजिक समीकरण, नेतृत्व की विश्वसनीयता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भावना भविष्य में इसकी चुनावी प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती है।

तीसरा हिस्सा उन ब्राह्मण परिवारों का है, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा सीमित है और आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर या दयनीय है। यह वर्ग वैचारिक या संगठनात्मक राजनीति की अपेक्षा स्थानीय नेतृत्व, क्षेत्रीय समीकरणों और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पहुंच के आधार पर अपनी चुनावी भागीदारी तय करता है। कई बार यह समुदाय राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श की बजाय स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेताओं के प्रभाव से अधिक प्रभावित होता है।

यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से बड़े पैमाने पर दूर हो रहे हैं। पिछले चुनावी अनुभव बताते हैं कि ब्राह्मण समुदाय ने भाजपा को अपनी पहली राजनीतिक प्राथमिकता के रूप में देखा है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना कि ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से बड़े पैमाने पर दूर हो रहे हैं, अभी जल्दबाज़ी होगी।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

राममंदिर चोरी- 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

अयोध्या के वकील पैरवी नहीं करेंगे, ट्रस्ट की बैठक अब 5 दिन पहले होगी

चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को अयोध्या छोड़ने की इजाजत न दी जाएः बार एसोसिएशन अध्यक्ष

अयोध्या/लखनऊ (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की गई। उनके बयान दर्ज किए गए। इसके बाद चंपत राय दिल्ली चले गए। वहीं अयोध्या के वकील पैरवी नहीं करेंगे और ट्रस्ट की बैठक अब 5 दिन पहले होगी।

इधर, पुलिस सोमवार सुबह साढ़े 10 बजे जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए सीबीआई की अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट लिए। अब यह जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। पुलिस ने बैंक के 2 कर्मचारियों को भी नोटिस दिया है।

इस बीच, सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। फिर कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे।

आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा- हालांकि, इससे पहले ही अयोध्या के वकीलों ने बड़ी बैठक की। इसमें फैसला लिया कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। साथ ही, चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के अयोध्या छोड़ने की मांग की। नहीं छोड़ने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा- जांच के तहत चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्र को अयोध्या छोड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कल अयोध्या जाएगा, प्रदर्शन करेंगे- कांग्रेस का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज को अयोध्या जाएगा। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा, सीतापुर सांसद राकेश राठौर, प्रयागराज सांसद उज्जवल रमण सिंह और बाराबंकी सांसद तनुज पूनिया शामिल होंगे।

अखिलेश बोले- राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कर दूसरे प्रदेश भेजा गया- अखिलेश यादव ने प्रयागराज में कहा- मर्यादा की जो बात है, इसमें बिल की जरूरत नहीं है। इसमें ईमानदारी की जरूरत है। आपकी नियत साफ हो, उसकी जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्रीराम से भी माफी नहीं मांगना चाहती।

अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई जांच की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के नेतृत्व में बहु-एजेंसी जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अगर गर्मी की छुट्टियों के बाद नियमित कामकाज शुरू होने पर सुनवाई होगी, तो आसमान नहीं गिर जाएगा।

अयोध्या के वकीलों का ऐलान- आरोपियों का केस लड़ने वाले पर 5 लाख का जुर्माना लगेगा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फैजाबाद एडवोकेट्स एसोसिएशन की बैठक हुई। इस दौरान अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा- मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा। अगर कोई ऐसा करता है, तो उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए 173 सीआरपीसी के तहत कोर्ट जाएंगे। बार एसोसिएशन सीबीआई जांच की भी मांग करेगा।

सिया ने केतन से 1 करोड़ लेकर चेतन को दिए

कैब ड्राइवर का दावा- सिया बाली नहीं जाना चाहती थी, केतन का पासपोर्ट गायब किया

पुणे (एजेंसी)। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, सिया ने केतन से शादी की शॉपिंग के नाम पर रू. 1 करोड़ लिए थे। इन पैसों से शॉपिंग नहीं की, बल्कि पूरी रकम प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी थी।

केतन-सिया की बाली प्री-वेडिंग ट्रिप के लिए 6 जून को उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब ड्राइवर वैभव जाधव का बयान सामने आया। उसके मुताबिक सिया बाली नहीं जाना चाहती थी। रास्ते में उसकी अपने भाई साहिल से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी।

वैभव ने बताया- कुछ देर बाद गाड़ी एक स्थान पर रुकी, जहां 4 अन्य लोग सवार हुए। बाद में गाड़ी फूड कोर्ट पर रुकी। सभी लोग खाने-पीने चले गए। कुछ देर बाद सिया आई। गाड़ी से कुछ सामान निकालकर अपने बूट में छिपा लिया और वापस चली गई। वैभव ने कहा कि मैंने सभी लोगों को एयरपोर्ट छोड़ा। बाद में कॉल आया कि केतन का पासपोर्ट कैब में छूट गया है। मैं एयरपोर्ट पहुंचा। गाड़ी की सभी ने तलाशी ली, लेकिन गाड़ी में पासपोर्ट नहीं मिला।

हरित विकास, निवेश और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हमारी सरकार : मुख्यमंत्री

देश में ग्रीन एनर्जी का पावर हाउस बन रहा है मध्यप्रदेश

निवेश के लिए विशेष मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 33 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। करीब 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर उतरे। पिछले ढाई वर्षों में वैश्विक कंपनियों का 9 हजार 200 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मध्यप्रदेश की धरती पर उतर रहा है।

भोपाल। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए मध्यप्रदेश ने सोमवार को हरित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी के साथ नीमच में 500 मेगावॉट क्षमता वाले नीमच सोलर पार्क तथा 450 मेगावॉट क्षमता वाले शाजापुर सोलर पार्क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास तथा नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने 1,553.98 करोड़ रुपये की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं विकास कार्यों का भी भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 550 मेगावॉट क्षमता वाला आगर सोलर पार्क भी निर्माणाधीन है, जिसकी इकाइयों के लिए 2.44 और 2.45 रुपये प्रति यूनिट की दरें प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद मध्यप्रदेश देश के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा तथा स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नीमच जिले में करीब 160 करोड़ रुपये की लागत से 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश का हरित विकास हमारा लक्ष्य है। हरित विकास के जरिए प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में निवेश लाने और इसके जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं।

नीमच के नए सोलर पार्क से मिलेगी 2.14 पैसे प्रति यूनिट बिजली, यह देश में सबसे सस्ती

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि नीमच में नए सोलर पार्क का शुभारंभ ऐतिहासिक अवसर है। इससे देश में सबसे सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी। नीमच की धरती ने प्रदेश को दो मुख्यमंत्री दिए। नीमच ने अफीम उत्पादन और नेत्रदान अभियान में शीर्ष स्थान हासिल कर अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संत कबीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सनातन संस्कृति में सूर्य देवता ऊर्जा के स्त्रोत हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत 19 मार्च से 30 जून तक कुंए, बावड़ी, नदी, तालाब और अन्य सभी जल स्त्रोतों के संरक्षण के उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। राज्य सरकार ने 3 महीने में 10 हजार करोड़ की राशि खर्च कर प्रदेशभर में 2 लाख से अधिक जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार किया है। जल गंगा संरक्षण अभियान में नीमच ने देश में 10वां और प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है।

अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की हुई पहली पूजा

उपराज्यपाल ने दर्शन किए, यात्रा 3 जुलाई से शुरू, सिक्योरिटी का ट्रायल हुआ

जम्मू-श्रीनगर (एजेंसी)। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 3 दिन पहले सोमवार को बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पूजा की। इस साल 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। कुल 57 दिनों तक यात्रा चलेगी। अधिकारियों के मुताबिक, 15 अप्रैल से अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा रूट के लिए रवाना होगा।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 30 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

ठाट-बाट छोड़ जमीन पर बैठे 'महाराज' सिंधिया

पूड़ी बेलने की स्पीड देख हैरान रह गईं महिलाएं, गाड़ी देने का किया ऐलान

गुना (नप्र)। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश के गुना में एक बेहद अनूठा और सादगी भरा रूप देखने को मिला है। गुना दौरे पर पहुंचे ग्वालियर राजपरिवार के मुखिया ने न केवल महिला स्व-सहायता समूहों की हौसलाअफजाई की, बल्कि प्रोटोकॉल और सुरक्षा घेरे को दरकिनार कर एक आम नागरिक की तरह महिलाओं के बीच बैठकर रसोई की कमान संभाल ली। उनके इस आत्मीय अंदाज को देखकर वहां मौजूद लोग और उनके समर्थक दंग रह गए।

यह दिलचस्प वाकया गुना के हरिपुर पंचायत क्षेत्र का है, जहां

केंद्रीय मंत्री आजीविका मिशन के तहत संचालित 'जीजी की पंचायत' नामक सामुदायिक संस्था का मुआयना करने पहुंचे थे। यहां महिलाओं को गर्मा-गरम पूड़ियां बनाते देख सिंधिया खुद को रोक नहीं पाए और उनके पास जमीन पर बैठ गए।

किचन में थामा बेलन, महिलाओं संग बेलीं पूड़ियां- रसोई में पहुंचकर उन्होंने तुरंत हाथ में बेलन थामा और धड़ाधड़ पूड़ियां बेलना शुरू कर दिया। सिंधिया के 25 वर्षों के लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला है। रसोई में महिलाओं की मदद करने के बाद उन्होंने वहां मौजूद पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों और क्षेत्र की प्रसिद्ध 'ड्रोन दीदी' किरण अहिरवार सहित चंदा बैरागी, सोना खान, मीनाक्षी और कामिनी शर्मा से सीधा संवाद किया और उनकी सफलता की कहानियां सुनीं।

महिला समूहों को लोडिंग वाहन देने का बड़ा ऐलान

इस सम्मेलन में महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने मंच से एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जिन स्वयं सहायता समूहों का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक होगा और जिन्हें अपने सामान को बाजार तक ले जाने में परेशानी आ रही है, उन्हें माल के परिवहन के लिए सांसद निधि से लोडिंग वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इस एहतियाती मदद से ग्रामीण महिलाओं का व्यापारिक दायरा और मजबूत होगा।

अरुणाचल की नाह जनजाति , जो करती है सीढ़ी वाली खेती, इनकी जमीनें चुपचाप 'हड़प' रहा चीन

नईदिल्ली/ईटानगर (एजेंसी)। अरुणाचल प्रदेश के वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से सटे गांवों पर चीन की बुरी नजर है। यहां की एक नाह जनजाति की एनएएच वेलफेयर सोसाइटी (एनडब्ल्यूएस) ने यह आरोप लगाया है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने बीते छह साल में अपर सुबनसिरी जिले के दूर-दराज इलाके 'टक्सिंग सर्कल' में भारतीय इलाके के अंदर सैन्य कैंप और सड़कें बना ली हैं। इससे भारत-चीन सीमा पर जमीन पर कब्जे को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अरुणाचल ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के अनुसार, नाह वेलफेयर सोसाइटी (एनडब्ल्यूएस) ने अपर सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर दावा किया है कि पीएलए ने उन कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है जिनका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से स्थानीय समुदाय करते रहे हैं। 26 जून को लिखे और एनडब्ल्यूएस के प्रेसिडेंट केरू चाडर के दस्तखत वाले पत्र में एनडब्ल्यूएस ने पांच जगहों असाफिला इलाके में ओयिंग (2445), चुजार्टा में पनियार, मारपन (मारनाफे), पोट्रांग झील और टिडिंगटांग की पहचान की है।

नाह समुदाय टैगिन जनजाति की उपजाति

सूत्रों के अनुसार, नाह समुदाय नाचो सर्कल के टक्सिंग इलाके में रहने वाली जनजाति टैगिन की उपजनजाति है। यह इलाका अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में है। साल 2,000 की जनगणना के दौरान यहां नाह की आबादी करीब 1,500 हुआ करती थी। इनकी साक्षरता करीब 30 फीसदी है।

नाह समुदाय की उत्पत्ति का इतिहास

नाह लोग नस्ल और भाषा, दोनों ही मामलों में तिब्बतियों की तुलना में टैगिन लोगों के ज्यादा करीब हैं। हालांकि, वे खुद को एक अलग समूह मानते हैं, जैसे लाइमकिंग में रहने वाले मारा लोग। हालांकि, दोनों ही जनजातियां मानती हैं कि उनकी और टैगिन लोगों की पूर्वज एक ही हैं ।सभी सरकारी जनगणनाओं में नगा लोगों को टैगिन लोगों के साथ ही गिना जाता है, क्योंकि नस्ल के आधार पर वे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

नाह समुदाय के लोग 'ना' जुबान बोलते हैं, जो चीन-तिब्बत भाषाई परिवार की ही सदस्य है। 'ना' भाषा को तागिन भाषा के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह जनजाति हिंदी या अंग्रेजी में भी बोल लेती है।

संक्षिप्त समाचार

पहाड़ से मैदान तक बाढ़-बारिश का कहर

- असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बाढ़ जैसे हालात

गुवाहाटी/जयपुर/लखनऊ/पटना/भोपाल (एजेंसी)। देश के पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी बारिश हो रही है। तीनों राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अरुणाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड की घटना में तीन की मौत हो गई।

वहीं असम के ढेमाजी जिले में केमी नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बह गया। पुल के बहने से केमी-पुराना जेलोम क्षेत्र का जोनाई सदर से सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। सिक्किम में जोंगू क्षेत्र में फी खोला नदी पर बना बेली ब्रिज बह गया।

22 राज्यों तक पहुंचे मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी,6 राज्यों में प्री-मानसून बारिश जारी- मानसून ने 24 जून तक देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया है, लेकिन बीते 5 दिन से इसकी रफ्तार धीमी पड़ी है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई

क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को कवर कर सकता है। 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में प्री-मानसून बारिश जारी है ।विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों और सिक्किम में आज तेज बारिश और कुछ जगहों के लिए बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।

कश्मीर का सरला भट्ट रेप-मर्डर केस में 35 साल बाद 737 पन्नों की चार्जशीट

- यासीन मलिक पर चलेगा एक और मुकदमा

श्रीनगर (एजेंसी)। आतंक के दौर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के दौरान सरला भट्ट की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। 35 साल बाद जम्मू-कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस केस में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस नृशंस हत्याकांड के आरोपियों में जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक भी आरोपी है। मलिक अभी दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि चार अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है।

1990 में जेकेएलएफ ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने का बड़ा आतंकी अभियान छेड़ रखा था। जेकेएलएफ के आतंकियों ने 18 अप्रैल 1990 को शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास से सरला भट्ट को अगवा कर लिया। फिर उनके साथ ऐसी बेरहमी की गई, जिसे आज भी कश्मीर में फैले आतंकवाद काला अध्याय का हिस्सा माना जाता है। सरला भट्ट के साथ रेप और मारपीट की गई। बाद में उन्हें श्रीनगर के उमर कॉलोनी, मालबाग में गोलियों से भून दिया। इसके बाद से दो दशक तक जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का तांडव होता रहा और सरला भट हत्याकांड की जांच फाइलों में अटकी रही।

भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन से राजस्व सेवाएँ होंगी अधिक प्रभावी, भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करना होगा आसान

भोपाल एवं सागर संभाग के 11 जिलों में जुलाई से शुरू होगा अगला चरण

भोपाल (नप्र)। प्रदेश के नागरिकों को भूमि संबंधी सरकारी अभिलेखों की सहज, त्वरित और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ पुराने भू-अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में चरणबद्ध रूप से डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से राज्य के लगभग 15 करोड़ पुराने भू-अभिलेख रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसके लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और डीबीईएस सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं। वर्ष 2008 में शुरू हुए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2016 से डीआईएलआरएमपी के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इसके तहत मॉडर्न रिकॉर्ड रूम (एमआरआर) के अंतर्गत पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की रूपरेखा तैयार की गई। योजना के फेज-1 (2013-2020) में लगभग 3,18,82,222 दस्तावेजों और फेज-2 (2021-22) में लगभग 2,39,24,462 दस्तावेजों की स्कैनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अब फेज-3 के तहत 15 करोड़ रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।

परियोजना में जिला स्तर पर अत्याधुनिक स्कैनिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। दस्तावेजों की सुरक्षित स्कैनिंग, मेटा-डाटा एंट्री और भोपाल में डीबीईएस आधारित डबल-बाइंड डेटा एंट्री की व्यवस्था की गई है। आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा ऑनलाइन गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा। अंतिम रूप से सत्यापित रिकॉर्ड 'भूलेख पोर्टल' पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।

योजना के प्रथम चरण में जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग के 12 जिलों में लगभग 2.70 करोड़ दस्तावेजों की शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूरी कर ली गई है। इन जिलों में डेटा एंट्री का कार्य निरंतर जारी है। दूसरे चरण में भोपाल एवं सागर संभाग के 11 जिलों में जुलाई 2026 से कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन से राजस्व व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। साथ ही नागरिकों को अपने भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन देखने और प्राप्त करने में आसानी होगी। इससे भूमि अभिलेखों का सुरक्षित संरक्षण सुनिश्चित होने के साथ राजस्व सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में भी वृद्धि होगी।

विश्व को पूर्णता प्रदान करना हमारा कार्य है : सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत

भारतीय शिक्षण मण्डल की अखिल भारतीय प्रान्त टोली बैठक का प्रेरणादायी समापन, नवीन वेबसाइट का लोकार्पण एवं 'विविभा' पुस्तक का विमोचन

बेंगलुरु। भारतीय शिक्षण मण्डल की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रान्त टोली बैठक का आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, बेंगलुरु में सफलतापूर्वक समापन हुआ। बैठक में देश के 43 प्रान्तों से आए लगभग 380 प्रतिनिधियों–कुलपति, शिक्षाविद्, शोधकर्ता, नीति-निर्माता, शिक्षक एवं कार्यकर्ताओं–ने सहभागिता की। समापन सत्र के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी रहे।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मनमोहन वैद्य जी, भारतीय शिक्षण मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द जोशी जी, अखिल भारतीय महामंत्री डॉ. भरत शरण जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री बी.आर. शंकरानन्द जी सहित अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं देशभर से आए प्रान्त प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का वृत्त तथा तीन दिवसीय चिंतन-मंथन के प्रमुख निष्कर्ष भारतीय शिक्षण मण्डल के अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री श्री सुनील शर्मा जी ने प्रस्तुत किए।

विश्व को सही बोध देने वाली शिक्षा का निर्माण करें- अपने मार्गदर्शन में प.पू. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने कहा कि आज विश्व अनेक संकटों और जटिल प्रश्नों से जूझ

रहा है। वर्तमान वैश्विक विचारधाराएँ और व्यवस्थाएँ जीवन को आंशिक रूप से देखती हैं, जबकि भारत की दृष्टि जीवन, समाज, प्रकृति और समस्त सृष्टि को एकात्म रूप में समझती है। उन्होंने कहा कि भारत की ज्ञान परम्परा का उद्देश्य किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं, बल्कि धर्म, संतुलन और समस्त मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है।

उन्होंने कहा, विश्व को पूर्णता प्रदान करना हमारा कार्य है। हमारी समग्र दृष्टि के आधार पर समस्त प्राणिमात्र के कल्याण के लिए भारत की वाणी को विश्व को सुनना ही होगा। यह समय की आवश्यकता भी है और अनिवार्यता भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय दृष्टि अन्य विचारों को अस्वीकार नहीं करती, बल्कि प्रत्येक समाज के अनुभवजन्य सत्य का सम्मान करती है। भारतीय चिंतन की 'अनेकता' की अवधारणा सभी दृष्टिकोणों का आदर करते हुए शास्त्रार्थ और संवाद के माध्यम से सत्य के व्यापक स्वरूप को समझने का मार्ग प्रदान करती है।

भारतीय शिक्षण मण्डल एक व्यापक सभ्यतागत दायित्व का वाहक- डॉ. भागवत जी ने कहा कि भारतीय शिक्षण मण्डल का कार्य कोई सीमित संगठनात्मक गतिविधि नहीं, बल्कि भारत के व्यापक सभ्यतागत दायित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कार्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण का प्रयास है जो मनुष्य के समग्र विकास को केंद्र में रखती है तथा केवल आजीविका या आर्थिक सफलता तक सीमित नहीं रहती।

उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षण मण्डल सदैव राजनीतिक दलों और उनकी सीमाओं से स्वतंत्र रहकर कार्य करता है।

निरंतरता, एकाग्रता और दूरदृष्टि से ही होगा परिवर्तन

राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण एकाग्रता और निरंतरता है। परिवर्तन केवल घोषणाओं और आयोजनों से नहीं आता, बल्कि सतत साधना, अनुशासित प्रयास और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में उन्होंने शिक्षाविदों से आह्वान किया कि वे केवल नीति के क्रियान्वयन तक सीमित न रहें, बल्कि यह भी विचार करें कि शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार का भारत निर्मित करना है। उन्होंने कहा कि दृष्टि के बिना कार्य अंधा होता है और कार्य के बिना दृष्टि निष्प्राण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत को एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया है, जिसे भारतीय अनुभव, भारतीय चिंतन और भारतीय शिक्षा मॉडल के आधार पर सार्थक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कौशल-आधारित शिक्षा की आवश्यकता है ताकि युवा रोजगार योग्य, उद्यमी और आत्मनिर्भर बन सकें। किन्तु संस्कारों से रहित कौशल समाज में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जिसमें कुशल हाथ, चिंतनशील मस्तिष्क और संवेदनशील हृदय का समन्वय हो।

तीन दिवसीय विशेष जनजागरण अभियान का शुभारंभ

भोपाल। ब्रह्माकुमारीज़ के सिक्योरिटी सर्विसेज विंग (SSW) द्वारा आयोजित 'स्व-सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण' तीन दिवसीय विशेष जनजागरण अभियान का शुभारंभ 28 जून की सायंकाल नीलबड़ स्थित सुख शांति भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में हुआ। उद्घाटन समारोह में 107 आरएएफ के कमांडेंट श्री जगदीश बलाई, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट

जनरल मिलन नायडू सहित सुरक्षा सेवाओं एवं समाज के अनेक गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आत्म-जागृति एवं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।

इसी अभियान की श्रृंखला में आज भोपाल के विभिन्न सुरक्षा एवं शैक्षणिक संस्थानों में विशेष जागरूकता एवं राजयोग मेडिटेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को आत्म-सशक्तिकरण, सकारात्मक चिंतन, तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन, नैतिक मूल्यों तथा आध्यात्मिक जीवनशैली के महत्व से अवगत कराया गया। वक्ताओं ने कहा कि जब व्यक्ति आत्मिक रूप से सशक्त बनता है, तभी परिवार, समाज और राष्ट्र भी सशक्त बनते हैं। वर्तमान समय में सुरक्षा बलों एवं युवाओं के लिए मानसिक स्थिरता, आत्मबल और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास अत्यंत आवश्यक है तथा राजयोग मेडिटेशन इन गुणों को विकसित करने का सरल एवं प्रभावी माध्यम है।

यूरोप में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, 1300 मौतें

सड़कें पिघलीं, स्कूल बंद, जंगलों में आग, पटरियां उखड़ी

पेरिस, लंदन, मैड्रिड/इटली (एजेंसी)। यूरोप इन दिनों रिकॉर्डतोड़ हीटवेव की चपेट में है। फ्रांस में भीषण गर्मी से करीब 1200 अतिरिक्त लोगों की मौत हुई है। हेल्थ एजेंसी ने बताया कि ये मौतें 24 जून से 27 जून के बीच हुईं। अतिरिक्त मौतों का मतलब है कि पिछले कुछ साल में हुई औसत मौतों की तुलना में इस बार करीब 1200 लोग ज्यादा मरे हैं।

हालांकि सरकार ने न ही पिछली बार और न ही इस बार का कोई सटीक आंकड़ा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों में 85 प्रतिशत बुजुर्ग हैं। सबसे अधिक मौतें घरों में हुईं।

खासकर राजधानी पेरिस और उसके आसपास के इलाकों वाले इलाके में ऐसे मामले ज्यादा सामने आए। वहीं, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क, इटली और स्विट्जरलैंड समेत 16 देशों में तापमान ने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

मीडिया सूत्रों के अनुमान के मुताबिक, रविवार को यूरोप के करीब 19.1 करोड़ लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान का सामना करना पड़ा। कहीं सड़कें पिघल रही हैं, कहीं स्कूल बंद करने पड़े हैं, तो कहीं जंगलों में भीषण आग भड़क उठी है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप का तापमान दुनिया के औसत तापमान की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य में ऐसी गर्मी की लहरें और अधिक बार आएंगी, ज्यादा समय तक रहेंगी।

फ्रांस के शैम्बैरी शहर के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में सुबह दुकान खुलते ही एयर कंडीशनर और पंखे खरीदने के लिए ग्राहकों में भगदड़ और धक्का-मुक्की देखने को मिली। पेरिस के एक सुपरमार्केट में इतनी ज्यादा में खरीदार पहुंचे कि पंखे, कूलर का स्टोर कुछ ही घंटे में खाली हो गया।

सेशेल्स में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी

गणेश मंदिर में पूजा भी की; महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर भारत रवाना हुए

विक्टोरिया (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने तीन दिवसीय सेशेल्स दौरे के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने विक्टोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। प्रधानमंत्री ने अरुल मिहु नवशक्ति विनायकर मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके बाद वह नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए है।

राज्यपाल श्री पटेल से मुख्यमंत्री ने की सौजन्य भेंट

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक भवन पहुंचकर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल श्री पटेल को मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होने, यूसीसी को लेकर मिल रहे व्यापक जन समर्थन एवं इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्य योजना से भी अवगत कराया। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन, गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, 4 कृषि उपजों को हाल ही में मिले जीआई टैग से संबंधित किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों एवं सरकार को मिली उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

बरकतउल्ला विवि का नाम कायम रखने का भाकपा द्वारा स्वागत

भोपाल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का नाम कायम रखने के निर्णय का स्वागत किया है तथा नाम बदलने के प्रस्ताव का प्रतिरोध करने वाले भाकपा सहित अन्य राजनीतिक दलों और जन संगठनों को बधाई दी है।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने बताया कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की कार्य परिषद द्वारा नाम बदलने का प्रस्ताव अनुचित और अक्षम्य था। उक्त प्रस्ताव से भारत के महान स्वाधीनता सेनानी और शिक्षाविद् प्रोफेसर बरकतउल्ला भोपाली और भारत के स्वाधीनता आन्दोलन के मूल्यों को अपमानित किया गया था।भाकपा तथा अन्य राजनीतिक दलों और जन संगठनों ने इसका प्रतिरोध कर विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रतिरोध और जन भावना को देखते हुए ही नाम बदलने का प्रस्ताव वापस लिया गया।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पुनः मांग की है कि भारत की प्रथम निर्वासित सरकार के प्रधान मंत्री, स्वाधीनता सेनानी और शिक्षाविद् प्रोफेसर बरकतउल्ला भोपाली की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल की जाए और प्रति वर्ष बरकतउल्ला भोपाली जी की स्मृति में शासकीय स्तर पर गरिमामय समारोह आयोजित किया जाए।

बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन 31 अक्टूबर तक

भोपाल (नप्र)। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। योजना के अंतर्गत बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के अध्ययनरत संतानों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को पात्र विद्यार्थियों तक योजना की जानकारी पहुंचाने तथा समय-सीमा में आवेदन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर एक जून से प्रारंभ हो चुके हैं। पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने महाविद्यालयों से अधिकाधिक पात्र विद्यार्थियों को योजना से जोड़ने और उनके आवेदनों का समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा है।

योजना के अंतर्गत कक्षा एक से लेकर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा एक से चौथी तक के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये, कक्षा 5 से 8 तक 1,500 रुपये, कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को 2,000 रुपये, कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को 3,000 रुपये तथा आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं डिग्री पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। वहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष तक की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है।

यह सहायता राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। योजना का लाभ बीड़ी श्रमिकों, लौह अयस्क, मैंगनीज एवं क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खदान श्रमिकों के पात्र बच्चों को दिया जाता है। यह योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा जारी रखने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने संत कबीर दास की जयंती पर किया नमन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान संत, समाज सुधारक कबीर दास की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संत कबीर दास जी ने सामाजिक कुरीतियों, आडम्बर एवं अंधविश्वास के विरुद्ध जनजागृति की। उनकी अमर कृतियां अनंतकाल तक समाज को लोककल्याण की दिशा देती रहेंगी।

छिंदवाड़ा-देवास में आंधी-बारिश, शबाब पर पातालपानी झरना

भोपाल-इंदौर समेत 43 जिलों में येलो अलर्ट, 40 जिलों में नहीं पहुंचा मानसून, 38 प्रतिशत कम बरसात

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव है। सोमवार को छिंदवाड़ा में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। देवास में आंधी के बाद आधे घंटे तक हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया। खंडवा, खरगोन और सीहोर में काले घने बादलों से दिन में ही अंधेरे जैसा माहौल बन गया। वहीं महू में बारिश के बाद पातालपानी झरना शबाब पर नजर आया।

मौसम विभाग ने उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला और बालाघाट में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां 24 घंटे में 4 इंच या इससे अधिक बारिश हो सकती है। वहीं, भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कहीं-न-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।

इसके साथ ही भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, आलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है।

वहीं, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, नीमच और मंदसौर में बूंदाबांदी का दौर रह सकता है। हालांकि, यहां अभी मानसून ने प्रवेश नहीं किया है। इससे पहले रविवार को प्रदेश में आंधी-बारिश का दौर जारी रहा। मंदसौर और रतलाम में तेज बारिश हुई। रतलाम में आधा इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। गुना, श्योपुर, बड़वानी, शाजापुर, सीहोर, मंदसौर, उज्जैन और छतरपुर समेत कई जिलों में भी बारिश हुई।

24 जून को प्रदेश में मानसून ने एंट्री ली थी। तब से अब तक 15 जिले ही मानसून ने कवर किए हैं। जबकि 40 जिलों में एंट्री नहीं हो पाई है। वहीं, प्रदेश की जून में अब तक हुई ओवरआल कुल बारिश भी 38 प्रतिशत कम है।

नौगांव में 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान

इधर, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के पांच बड़े शहरों में उज्जैन का अधिकतम तापमान सबसे कम 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इंदौर में 33.8 डिग्री, भोपाल में 34.6 डिग्री, जबलपुर में 38.3 डिग्री और ग्वालियर में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान खंडवा में 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खरगोन में 30.8 डिग्री, छिंदवाड़ा में 32.1 डिग्री, पचमढ़ी में 32.6 डिग्री, रतलाम में 33.2 डिग्री, सिवनी में 33.4 डिग्री, रायसेन में 33.6 डिग्री, बैतूल में 34 डिग्री और धार में 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, नौगांव में सबसे अधिक 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ दायर याचिका खारिज

जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा-एनएसए लगाने का आदेश नहीं दे सकती अदालत,मांगी राहतें स्वीकार नहीं की जा सकतीं

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा और याचिका में मांगी गई राहतें कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित किया।

जबलपुर निवासी अधिवक्ता अभिषेक दुबे ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 23 नवंबर 2025 को अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज को लेकर कथित रूप से जातिसूचक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। याचिका में कहा गया था कि इससे समाज में आक्रोश और वैमनस्य का माहौल बना।

याचिकाकर्ता ने संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा ब्राह्मण समाज के हित में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी।

राहत पर अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं- हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, उस संबंध में एफआईआर पहले से दर्ज है। इसलिए इस राहत पर अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करना संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का विशेषाधिकार है। न्यायालय सरकार को किसी विशेष व्यक्ति पर एनएसए लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

भारत सरकार को पक्षकार नहीं बनाया - आईएएस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भारत सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है। चूंकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार आवश्यक पक्ष है, इसलिए इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा-ये कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र

ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश या नीति बनाने की मांग को भी अदालत ने अस्वीकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विशेष समुदाय के लिए नीतियां बनाना कार्यपालिका और विधायिका का क्षेत्राधिकार है, न्यायपालिका का नहीं।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिका में मांगी गई राहतें स्वीकार नहीं की जा सकतीं। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी कथित अपराध या सेवा नियमों के उल्लंघन के संबंध में कानून के तहत कोई कार्यवाही बनती है, तो कानून अपना काम करेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

कलियासोत डैम में डूबने से नाबालिग की मौत

दोस्तों के साथ घूमने गया था, दो घंटे बाद मिला शव

भोपाल (नप्र)। राजधानी के चूनाभट्टी थाना क्षेत्र स्थित कलियासोत डैम में दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 17 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक अपने तीन दोस्तों के साथ घूमने और फोटो खिंचवाने डैम पहुंचा था। प्रतिबंधित क्षेत्र में पानी के भीतर फोटो खिंचवाते समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में समा गया।करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद गोताखोरों ने उसका शव बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार, जाटखेड़ी (मिसरोद) निवासी अंगद दांडे (17) पुत्र संतोष दांडे रविवार को अपने तीन दोस्तों के साथ कलियासोत डैम गया था। सभी दोस्त पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर ढलान वाले हिस्से में पानी में उतरकर फोटो खिंचवा रहे थे। शुरुआती हिस्से में पानी घुटनों तक था, लेकिन कुछ कदम आगे ही गहराई अधिक होने के कारण अंगद संतुलन खो बैठा और डूब गया। उसे और उसके साथ मौजूद किसी भी दोस्त को तैरना नहीं आता था।

मदद के लिए दोस्तों ने मचाया था शोर

घटना के बाद दोस्तों ने शोर मचाया, लेकिन आसपास कोई मदद के लिए नहीं था। इसके बाद वे पास स्थित पुलिस चौकी पहुंचे और सूचना दी। पुलिस ने तत्काल गोताखोरों को बुलाया। लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद किशोर का शव बाहर निकालकर पोस्टमार्ट्म के लिए भेजा गया।

चेतावनी के बावजूद लोग पहुंच रहे प्रतिबंधित क्षेत्र

पुलिस ने बताया कि जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां मगरमच्छों की मौजूदगी और गहरे पानी को लेकर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही नगरीय प्रशासन की मदद से फेंसिंग और स्टॉपर भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद लोग सुरक्षा इंतजामों को नजरअंदाज कर रास्ता बनाकर डैम तक पहुंच जाते हैं, जिससे लगातार हादसों का खतरा बना रहता है।

इधर, गड्ढे में डूबने से तीन साल की मासूम की मौत

कजलीखेड़ा थाना क्षेत्र के धोली खदान के पास पानी से भरे गड्ढे में डूबने से तीन वर्षीय मासूम देविका की रविवार दोपहर मौत हो गई। उसके पिता राज रैकवार ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे थे, जबकि बच्ची घर के पास खेल रही थी।खेलते-खेलते वह तीन से चार फीट गहरे पानी के गड्ढे में गिर गई। काफी देर तक नजर नहीं आने पर परिजनों ने तलाश शुरू की और उसे गड्ढे से निकालकर निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्ट्म के लिए भेज दिया है।

बेंगलुरू में मिली 7 दिन से लापता नाबालिग

दो महीने पहले भी घर से गायब हुई थी छात्रा, तब चित्रकूट में मिली थी

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में सात दिन पहले महाराजपुरा से लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को पुलिस ने बेंगलुरू से बरामद कर लिया है। नाबालिग दो महीने पहले अप्रैल 2026 में भी लापता हो गई थी, तब पुलिस ने चित्रकूट से उसे बरामद किया था। इस बार भी पुलिस ने बिना देर किए सीसीटीवी कैमरे खंगाले और रूट मैपिंग कर नाबालिग को ट्रैस कर बरामद किया है। नाबालिग ने घर जाने से इनकार कर दिया है, जिस पर उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है।

21 जून को शताब्दीपुरम में घर से हुई थी लापता- महाराजपुरा थाना पुलिस बताया कि 21 जून को शताब्दीपुरम में रहने वाली एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। परिजन ने अपने स्तर पर तलाश करने के बाद महाराजपुरा थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। लापता नाबालिग मूल रूप से भिंड की रहने वाली है, लेकिन पढ़ाई के लिए अभी महाराजपुरा इलाके में रह रहे थे। मामला नाबालिग बच्ची के लापता होने से जुड़ा था, इसलिए सीएसपी महाराजपुरा नागेंद्र सिंह सिकरवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक यशवंत गोयल ने तत्कासल एक सर्च टीम का गठन किया।

ऐसे हुई बरामदगी- पुलिस टीम ने शताब्दीपुरम और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कुछ संदेहियों को राउंडअप कर पूछताछ की और अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया। पुलिस की इस चौतरफा घेराबंदी और त्वरित कार्रवाई के चलते रविवार शाम को पुलिस ने रूट मैपिंग कर छात्रा का पता लगाया और उसे शहर के पास से ही बरामद कर लिया है। पुलिस छात्रा को बरामद कर लाई, लेकिन उसने घर जाने से मना कर दिया है। जिस कारण फिलहाल उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस जांच और काउंसलिंग के दौरान इस बालिका से जुड़ा एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया।

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के कॉन्सुल जनरल ने की शिष्टाचार भेंट

मध्यप्रदेश पुलिस के नवाचारों, सेफ क्लिक 2.0 एवं नशे से दूरी है जरूरी अभियान पर हुई सार्थक चर्चा

भोपाल (नप्र)। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के मुंबई स्थित कॉन्सुल जनरल श्री नबील ताउआती ने आज पुलिस मुख्यालय, भोपाल में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कॉन्सुल जनरल के साथ मुंबई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार श्री कौस्तुभ परिहार एवं कृषि सलाहकार श्री प्रसाद पारते भी उपस्थित रहे।

भेंट के दौरान पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा ने मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग, तकनीकी नवाचार एवं नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से संचालित राज्यव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस अभियान के माध्यम से नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं विभिन्न संस्थानों तक व्यापक स्तर पर साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता पहुंचाई जा रही है।

पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश सरकार एवं मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित नशे से दूरी है जरूरी अभियान की भी जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने, समाज में जागरूकता बढ़ाने तथा मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रदेशभर में समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के माध्यम से नशामुक्त एवं सुरक्षित समाज के निर्माण की दिशा में मध्यप्रदेश पुलिस निरंतर कार्यरत है।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच जनसुरक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा, जागरूकता अभियानों तथा आपसी सहयोग एवं अनुभवों के आदान-प्रदान जैसे विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। कॉन्सुल जनरल श्री नबील ताउआती ने मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा जनहित में संचालित नवाचारों एवं व्यापक जन-जागरूकता अभियानों की सराहना करते हुए भविष्य में पारस्परिक सहयोग एवं संवाद को और सुदृढ़ बनाने की इच्छा व्यक्त की।

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा इस प्रकार के सौहार्दपूर्ण संवाद से आपसी समझ एवं सहयोग को नई दिशा मिलेगी तथा जनहित एवं सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ज्ञान एवं अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

संपादकीय

यूरोप में गर्मी से हाहाकार..!

इस बार समूचे यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। अमूमन ठंडे समझे जाने वाले देश जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन समेत 16 देशों में भयंकर तापमान से सड़कें पिघलने लगीं हैं, जंगल सुलग उठे हैं, स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा फ्रांस का है, जहां भीषण गर्मी के कारण अब 1 हजार लोगों की मौत होना बताया जा रहा है और इनमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं। ये मौतें महज तीन दिनों के भीतर हुई हैं। हालांकि सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। ज्यादातर मौतें घरों में ही हुई हैं। पिछले दिनों पेरिस में तापमान 44 डिग्री तक दर्ज किया गया। इतनी गर्मी तो भारत जैसे गर्म देशों में भी असहनीय मानी जाती है, ऐसे में अमूमन 15-20 डिग्री में जीने वाले यूरोपवासियों के लिए तो किसी सजा से कम नहीं है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि यूरोपवासी एसी या कूलरों की दुकानों पर टूटे पड़े हों। ब्रिटेन में जून में गर्मी का 50 साल पुराना रिकॉर्ड 3 बार टूटा। वहां सरकार तीन दिनों तक 'रेड वार्निंग' जारी करनी पड़ी है। दक्षिणी इंग्लैंड में तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस जून का नया रिकॉर्ड है। ब्रिटेन के इतिहास का सबसे अधिक तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस है, जो जुलाई 2022 में दर्ज किया गया था। यह रिकॉर्ड इस साल टूट सकता है। भयंकर गर्मी के कारण इन देशों में बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सांस की तकलीफ के मरीजों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई है। इसके कारण कई बड़े अस्पतालों को इमरजेंसी घोषित करना पडी है। गर्मी से लोहे की रेलवे पटरियां फैल रही हैं और उनके मुड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसके कारण ट्रेनों की रफ्तार पर सख्त स्पीड लिमिट (60 मील प्रति घंटा) लगा दी गई है। इतना ही नहीं पानी बचाने के लिए कई इलाके में पाइप के जरिए बगीचों और कारों पर पानी डालने (होजपाइप) पर रोक लगा दी गई है। यूरोप में भी स्पेन सबसे ज्यादा तप रहा है। वहां एंडुजार शहर में तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। पिछले 4 दिनों में गर्मी के कारण देश में 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। जर्मनी का हाल भी बुरा है। वहां कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। यही स्थिति डेनमार्क की भी है। जबकि स्विट्जरलैंड में गर्मी से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। कुल मिलाकर यूरोप में राष्ट्रीय आपदा की स्थिति है। वहां घरों की बनावट भी अलग होती है। कोई क्रॉस वेंटीलेशन नहीं होता, जिससे लोगों की दम घुटने से मौतें हो रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप का तापमान दुनिया के औसत तापमान की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य में ऐसी गर्मी की लहरें और अधिक बार आएंगी, ज्यादा समय तक रहेंगी। यह सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। दुनिया इस खतरे को समझ रही है, लेकिन उसे मानना नहीं चाहती। नतीजा यह है कि यूरोप और पश्चिम एशिया अभी भी अपने क्षुद्र स्वार्थों के कारण युद्धों में उलझे हैं, इस का कारण भी धरती का तापमान बढ़ रहा है। पर्यावरण को नष्ट कर इंसान कितनी बड़ी गलती कर रहा है, यह उसकी शायद तब आएगी, जब हाथ में करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पश्चिमी देश और अमेरिका हैं। जब यूरोप और अमेरिका में जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाएगा, तब उनकी इसका महत्व उनकी समझ आएगा।

पर्यावरण

राज कुमार सिन्हा

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

अल नीनो: भारत के भविष्य पर मंडराता संकट

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण अल नीनो की तीव्रता और अनिश्चितता दोनों बढ़ रही हैं, जिससे भारत जैसे मानसून-निर्भर देश के लिए इसके खतरे और गंभीर हो गए हैं। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर की व्यापारिक पवनें (ट्रेड विन्डस) गर्म जल को पश्चिम की ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन जब ये पवनें कमजोर पड़ जाती हैं, तब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का समुद्री तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसी स्थिति को अल नीनो कहा जाता है। यह घटना वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को बदल देती है और भारतीय मानसून को कमजोर कर सकती है। भारत की लगभग आधी कृषि भूमि आज भी वर्षा आधारित है। देश के जलाशय, भूजल पुनर्भरण, बिजली उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर हैं। अल नीनो सीधे मानसून को प्रभावित करता है, इसलिए इसका प्रभाव बहुआयामी होता है।

ता जा पूर्वानुमानों के अनुसार, 2026 के आखरी महीनों में एक अत्यधिक शक्तिशाली अल नीनो उभरने की पूरी आशंका है।वैज्ञानिकों ने भारत पर पड़ने वाले इस संभावित अल नीनो के प्रभाव को चार प्रमुख तिमाहियों में विभाजित किया है, जो देश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने पर असर डालेगा। पहला जून से सितंबर 2026 में मॉनसून पर संकट और बुवाई में देरी, दूसरा अक्टूबर से दिसंबर तक खरीफ फसलों को नुकसान और बढ़ती महंगाई और तीसरा जनवरी से मार्च 2027 तक गर्म सर्दियां और रबी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल है। प्रशांत महासागर में विकसित होने वाली जलवायु घटना अल नीनो केवल एक मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि भारत की कृषि, जल, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालने वाली वैश्विक जलवायु प्रक्रिया है।

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण अल नीनो की तीव्रता और अनिश्चितता दोनों बढ़ रही हैं, जिससे भारत जैसे मानसून-निर्भर देश के लिए इसके खतरे और गंभीर हो गए हैं। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर की व्यापारिक पवनें (ट्रेड विन्डस) गर्म जल को पश्चिम की ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन जब ये पवनें कमजोर पड़ जाती हैं, तब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का समुद्री तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसी स्थिति को अल नीनो कहा जाता है। यह घटना वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को बदल देती है और भारतीय मानसून को कमजोर कर सकती है। भारत की लगभग आधी कृषि भूमि आज भी वर्षा आधारित है। देश के जलाशय, भूजल पुनर्भरण, बिजली उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर हैं। अल नीनो सीधे मानसून को प्रभावित करता है, इसलिए इसका प्रभाव बहुआयामी होता है।

अल नीनो का सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है। विगत कई वर्षों के मानसून अध्ययन से पता चलता है कि भारत में बड़े सूखे अल नीनो आए हैं। मानसून कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा घटती है और उसका वितरण भी असमान हो जाता है। देर से मानसून आगमन लंबे 'ड्राई स्पेल 'हैं और अचानक अत्यधिक वर्षा की घटनाएं

सूखा और बाढ़ दोनों का जोखिम बढ़ाता है, अर्थात् जलवायु परिवर्तन के कारण अब 'कम बारिश' के साथ 'अत्यधिक बारिश' की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। यानी मानसून कमजोर हो सकता है लेकिन कुछ दिनों में अत्यधिक बारिश से विनाशकारी बाढ़ भी आ सकती है।पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाले उतराखंड के इशांत अग्रवाल का कहना है कि आमतौर पर मानसून के इस तरह अचानक रूठ जाने या थम जाने का सारा दोष 'ग्लोबल वॉर्मिंग', अल-नीनो या समुद्र के गर्म होने के सिर मढ़ दिया जाता है। लेकिन भारत के बेहतरीन वैज्ञानिकों की लगातार आ रही रिसर्च ने एक ऐसा कड़वा सच सामने रखा है, जिसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम खुद हैं। विज्ञान कहता है कि मानसून के इस तरह कमजोर होने की एक बहुत बड़ी वजह हमारे ठीक सामने है। बढ़ते

शहरीकरण, वनों की कटाई, आर्द्रभूमियों के विनाश और एकल फसल आधारित कृषि पद्धतियों ने स्थानीय जल चक्र को कमजोर किया है। इससे भूमि की नमी घट रही है और मानसून के पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि भूमि उपयोग में परिवर्तन और वनस्पति आवरण में कमी भी मानसून की अनिश्चितता बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कारक बनते जा रहे हैं।

भारत को अल नीनो के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनानी होगी। इसमें वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जलग्रहण क्षेत्र विकास, फसल विविधीकरण, सूखा-रोधी बीजों को बढ़ावा, रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करना, प्राकृतिक एवं जलवायु-अनुकूल कृषि को प्रोत्साहित करना, स्थानीय जल निकायों का संरक्षण और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। साथ ही शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाकर और हीट एक्शन प्लान लागू करके गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लगभग 315 जिलों में वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है और इन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था बहुत सीमित है। इनमें से अधिकांश जिले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के हैं। भारत सरकार ने किसानों के हित और खेती को सुरक्षित रखने के लिए जल प्रबंधन, बीज की उपलब्धता, और वैकल्पिक फसलों पर रणनीति तैयार की गई है।315 संवेदनशील जिलों को चिन्हित कर विशेष रूप से खरीफ फसलों जैसे धान और मक्का की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। कम बारिश होने की स्थिति में किसानों को कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों और सूखे के प्रति सहनशील बीजों की आपूर्ति की जा रही है।राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई गई हैं, जो बारिश, जल स्तर और बीज-खाद की आपूर्ति पर लगातार नजर रख रही हैं।जानकार बताते हैं कि मध्यप्रदेश का धार, झाबुआ, बड़वानी, नीमच, रतलाम, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, शिवपुरी, मंडला, सतना, बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा जिले ज्यादा प्रभावित होंने की संभावना है।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि अभी भी केंद्रीय भूमिका निभाती है। कमजोर मानसून का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ता है। धान, गेहूं, दाल, गन्ना और तिलहन उत्पादन में गिरावट होती है, खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित और सिंचाई लागत में वृद्धि होती है। हाल के वर्षों में सरकार को चीनी निर्यात रोकने जैसे कदम उठाने पड़े क्योंकि कमजोर मानसून से गन्ना उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ी है। जल संकट और भूजल पर दबाव कम वर्षा का सीधा असर नदियों, बांधों और भूजल स्तर पर पड़ता है।भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड और तेलंगाना पहले से ही भूजल दोहन के गंभीर संकट से जूझ रहा है। अल नीनो इस संकट को और गहरा कर सकता है। अल नीनो वाले वर्षों में वैश्विक तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है।

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बनने वाले अल नीनो वैश्विक तापमान को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा सकता है। इस कारण लंबी और तीव्र हीटवेव, शहरी 'हीट आइलैंड' प्रभाव,श्रमिकों की कार्यक्षमता में कमी, लू से मौतें होगी और गरीब और असंगठित क्षेत्र के मजदूर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अल नीनो का प्रभाव सभी वर्गों पर समान नहीं पड़ता। छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, महिलाएं, आदिवासी समुदाय, मछुआरे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इससे ग्रामीणों का पलायन, आय असमानता और सामाजिक असुरक्षा बढ़ने का खतरा पैदा होता है। कम जल उपलब्धता और बढ़ती गर्मी ऊर्जा क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। कमजोर मानसून का असर जीडीपी वृद्धि पर भी पड़ सकता है क्योंकि भारत की बड़ी आबादी कृषि आधारित है। अल नीनो समुद्री तापमान को बढ़ाकर समुद्री जैव विविधता को प्रभावित करेगा। इस कारण समुद्री खाद्य श्रृंखला बाधित और छोटे मछुआरों की आय प्रभावित होगी। भारत के तटीय राज्यों विशेषकर तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और केरल पर इसका असर अधिक पड़ सकता है।

पहले अल नीनो एक प्राकृतिक चक्र था, लेकिन अब मानवजनित जलवायु परिवर्तन इसकी तीव्रता बढ़ा रहा है। प्रशांत महासागर में पनप रहा अल नीनो भारत के लिए केवल मौसम संबंधी घटना नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल संकट, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा राष्ट्रीय खतरा है। जलवायु परिवर्तन ने इस खतरे को और जटिल बना दिया है। यदि भारत ने समय रहते जल, कृषि और ऊर्जा नीतियों में व्यापक परिवर्तन नहीं किए, तो भविष्य में अल नीनो जैसी घटनाएँ करोड़ों लोगों की आजीविका और जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं।

न्यायिक खामी

राजेश कुमार

(दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता)

वैश्विक न्यायशास्त्र की कसौटी पर ईडी और विधिक सुधार

सामान्य कानून का सिद्धांत कहता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, व्यक्ति निर्दोष है और अपराध साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। लेकिन, भारत में ईडी के मामलों में यह भार आरोपी पर डाल दिया गया। यानी, यदि आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तो आपको अदालत में यह साबित करना होगा कि आप निर्दोष हैं। इसकी तुलना यदि हम अमेरिका और यूके से करें, तो वहां की कानूनी व्यवस्था अभी भी 'बेगुनाही के अनुमान' के पारंपरिक सिद्धांत पर टिकी है। वहां अभियोजन पक्ष को संदेह से परे यह साबित करना होता है कि आरोपी ने अपराध किया है।

भा रत के समकालीन राजनीतिक और कानूनी विमर्श में यदि कोई एक शब्द सबसे अधिक गूंजता है, तो वह है 'ई-डी' यानी प्रवर्तन निदेशालय। कभी सफेदपोश अपराधों की जांच करने वाली एक शांत एजेंसी के रूप में जानी जाने वाली यह संस्था आज देश के शक्ति-केंद्र के रूप में उभरी है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पी-एम-एल-ए) के कठोर प्रावधानों ने ई-डी को वे शक्तियां प्रदान की हैं, जो शायद ही किसी अन्य जांच एजेंसी के पास हों। लेकिन जब हम वैश्विक पटल पर नजर डालते हैं, तो अमेरिका की फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क और यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी जैसी संस्थाएं एक अलग कहानी बयां करती हैं। भारत में ईडी की प्रकृति पुलिस और राजस्व विभाग का एक अनूठा मिश्रण है। यह न केवल वित्तीय अनियमितताओं की जांच करती है, बल्कि इसके पास गिरफ्तार करने, संपत्ति कुर्क करने और छापेमारी करने जैसी व्यापक पुलिस शक्तियां भी हैं। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका की फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क मुख्य रूप से एक 'वित्तीय खुफिया इकाई'के रूप में कार्य करती है। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क का प्राथमिक कार्य डेटा का विश्लेषण करना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है, न कि सीधे सड़कों पर उतरकर छापेमारी करना। वहां जांच का जमीनी काम एफबीआई जैसी एजेंसियां करती हैं।

वहीं, यूनाइटेड किंगडम की नेशनल क्राइम एजेंसी नागरिक और आपराधिक दोनों तरह की शक्तियों से लैस है। नेशनल क्राइम एजेंसी का ढांचा 'बहु-विषयक' है, जो इसे संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लचीला रुख अपनाने की अनुमति देता है। भारत में ई-डी की समस्या यह है कि यह 'राजस्व' की आड़ में पुलिस शक्तियों का प्रयोग करती है, जिससे अक्सर यह विवाद उत्पन्न होता है कि क्या यह एजेंसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संरक्षणों से ऊपर है। भारतीय पीएमएलए की धारा 24 एक अत्यंत विवादास्पद प्रावधान है। सामान्य कानून का सिद्धांत कहता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, व्यक्ति निर्दोष है और अपराध साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। लेकिन, भारत में ईडी के मामलों में यह भार आरोपी पर डाल दिया गया है। यानी, यदि आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तो आपको अदालत में यह साबित करना होगा कि आप निर्दोष हैं। इसकी तुलना यदि हम अमेरिका और यूके से करें, तो वहां की कानूनी व्यवस्था अभी भी 'बेगुनाही के अनुमान' के पारंपरिक सिद्धांत पर टिकी है। वहां अभियोजन पक्ष को संदेह से परे यह साबित करना होता है कि आरोपी ने अपराध किया है। भारत का यह उल्टा पिरामिड ढांचा अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर देता है, जहां आरोपी महीनों तक जेल में केवल इसलिए रहता है क्योंकि वह अपनी बेगुनाही का प्रारंभिक साक्ष्य नहीं दे पाता। एक और महत्वपूर्ण बिंदु 'बयानों की स्वीकार्यता' का है। भारतीय कानून के अनुसार, पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होता (साक्ष्य अधिनियम की धारा 25)। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 'विजय मदनलाल चौधरी' मामले में यह व्यवस्था दी कि ई-डी अधिकारी 'पुलिस अधिकारी' नहीं हैं। इसलिए, ई-डी के समक्ष दिया गया बयान अदालत में आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह व्यवस्था वैश्विक मानकों से काफी भिन्न है। अमेरिका में 'मिरांडा राइट्स' के तहत किसी भी एजेंसी के सामने दिया गया बयान तब तक मान्य नहीं होता जब तक आरोपी को उसके चुप रहने के अधिकार की जानकारी न दी गई हो। यूके में भी मानवाधिकार सुरक्षा के कड़े नियम हैं, जो किसी भी एजेंसी को डरा-धमका कर या दबाव में बयान लेने से रोकते हैं। भारत में ई-डी को मिली यह शक्ति उसे एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर देती है जहां 'आत्म-दोषारोपण' के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा (अनुच्छेद

20(3)) कमजोर पड़ती दिखाई देती है। आंकड़े किसी भी एजेंसी की सफलता की कहानी कहते हैं। भारत में ई-डी की दोषसिद्धि दर काफी चर्चा का विषय रही है, जो कि ऐतिहासिक रूप से 1% से भी कम रही है। हजारों मामलों और सैकड़ों गिरफ्तारियों के बावजूद, अंतिम सजा तक पहुंचने वाले मामलों की संख्या नगण्य है। इसका कारण अक्सर जटिल कानूनी प्रक्रिया और जांच में लगने वाला लंबा समय बताया जाता है।

इसके विपरीत, अमेरिका की फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क और यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी का ध्यान केवल जेल भेजने पर नहीं, बल्कि 'रिकवरी' पर अधिक होता है। वे वित्तीय प्रणाली को स्वच्छ रखने और अवैध धन को जब्त करने में अधिक सफल रही हैं। वहां की न्यायिक प्रक्रिया तेज है और एजेंसियां केवल उन्हीं मामलों को कोर्ट तक ले जाती हैं जहां साक्ष्य ठोस हों। भारत में, प्रक्रिया ही अक्सर सजा बन जाती है, जहां सालों तक आरोपी बिना किसी दोषसिद्धि के न्यायिक हिरासत या कानूनी उलझनों में फंसा रहता है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने के लिए कुछ मौलिक विधिक और संस्थागत सुधार अनिवार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुधार स्वतंत्र निरीक्षण से संबंधित है; एजेंसी की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसे वर्तमान राजस्व विभाग के नियंत्रण से मुक्त कर एक 'सांविधिक स्वायत्त निकाय' के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए। इसकी सीधी जवाबदेही संसद के प्रति होनी चाहिए, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप कम होंगे और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, समयबद्ध जांच के सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक है ताकि संपत्तियों की कुर्की और जांच की प्रक्रिया वर्षों तक न खिंचे। कानून में अस्थायी कुर्की और अंतिम न्यायिक निर्णय के बीच एक निश्चित समय सीमा अनिवार्य होनी चाहिए, जिससे निर्दोष व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता बाधित न हो।

संस्थागत ढांचे के साथ-साथ, पी-एम-एल-ए की कठोर शक्तियों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के मानवीय सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करना समय की मांग है। गिरफ्तारी के आधारों और बयानों की स्वीकार्यता को संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए ताकि कानूनी प्रक्रिया स्वयं में एक 'सजा' न बन जाए। अंततः, जांच की गुणवत्ता और दोषसिद्धि दर में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ कैडर का विकास अत्यंत आवश्यक है। केवल प्रतिनियुक्ति पर आए पुलिस अधिकारियों के स्थान पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डाटा एनालिस्ट्स, फॉरेंसिक ऑडिटर्स और साइबर विशेषज्ञों की स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। आधुनिक वित्तीय अपराधों को सुलझाने के लिए केवल कानूनी शक्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों और तकनीकी विशेषज्ञता के समन्वय से ही वास्तविक अपराधियों को प्रभावी ढंग से सजा दिलाई जा सकती है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे अपराधों से निपटने के लिए ईडी जैसी एक सशक्त एजेंसी की आवश्यकता है। लेकिन, शक्ति के साथ जवाबदेही का होना भी अनिवार्य है। वैश्विक तुलना यह स्पष्ट करती है कि जहां विकसित लोकतंत्रों में वित्तीय जांच एजेंसियां 'सिस्टम' को सुधारने और 'साक्ष्य' पर आधारित काम करती हैं, वहीं भारतीय तंत्र में 'प्रक्रियात्मक कठोरता' अधिक है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कानून की वास्तविक शक्ति उसकी दंडात्मक कठोरता में नहीं, बल्कि उसके न्यायसंगत होने में निहित है। प्रवर्तन निदेशालय को अपनी छवि एक 'दंडात्मक अस्त्र' के बजाय 'संवैधानिक मर्यादाओं' के रक्षक के रूप में पुनर्परिभाषित करनी होगी, क्योंकि जब तक विधिक प्रक्रिया और दंड के बीच का अंतर धुंधला रहेगा, न्याय की अवधारणा अधूरी ही रहेगी। एक शानदार विधिक तंत्र वही है जो अपराधी के मन में भय और निर्दोष के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करे। विकसित भारत का मार्ग केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं, बल्कि एक ऐसी पारदर्शी विधिक व्यवस्था से होकर गुजरता है जहाँ 'कानून का शासन' हो, न कि 'कानून के द्वारा शासन'। अब समय आ गया है कि हम अपनी जांच प्रणालियों को मात्र गिरफ्तारी की संख्या से नहीं, बल्कि दोषसिद्धि दर में सुधार, साक्ष्य के भार जैसे प्रावधानों पर पुनर्विचार और वैश्विक मानवाधिकार मानकों के साथ सामंजस्य बिठाकर 'विश्वसनीयता' प्रदान करें।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

मुकेश नेमा

लेखक मप्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

अब बिना बाल वाले लड़के भयभीत हैं

प च्चीस पचास साल पहले तक लड़कों का जीवन आसान था। पति बनने के लिए लड़का होकर पैदा होना ही काफी था। आड़े तिरछे, टूटे-फूटे, नाटे-मोटे हर तरह के लड़के आसानी से ठिकाने लग जाते थे,ऐसे में कोई उनका सर टटोले, बाल गिने, बालविहीन होने की वजह से कोई बालक अपनी मंगेतर के हाथों सिधार जाए, ऐसी बातें ख्वाब मे आने लायक़ जैसी भी नहीं थी।

अब लड़के भयभीत हैं। अपने बाप दादाओं जैसे अच्छे दिन उनके नसीब में नहीं। तब सर पर मौजूद बाल पचास साठ की उम्र तक ठहरे भी रहते थे, अब पच्चीस के आसपास चला चली शुरू हो जाती है इनकी। जुल्फ़ों की खेती बनी रहे इसका क़रीब बाईस हज़ार करोड़ का कारोबार है आजकल इस ग़रीब देश में। हम हिंदुस्तानी अपनी इतनी सारी गाढ़ी कमाई तेल और शैम्पुओ में केवल इसलिये बहा देते है क्योंकि हमारे यहाँ की बाईस फ़ीसदी महिलाओं के साथ साथ तीस फ़ीसदी पुरूषों को भी यह ग़लतफ़हमी है कि सर पर बालों की मौजूदगी खूबसूरती का दूसरा नाम है।

बालों को बचाये रखने का क़रीब साढ़े तीन अरब डॉलर सालाना का कारोबार है इस धरती पर। बहुत से छोटे मोटे देशों के साल भर का खर्च भी कम है इससे। मलेरिया से बचने के लिये पूरी दुनिया जितना खर्च करती है ये उससे भी ज़्यादा है। इससे ये बात साफ़ है कि लोग गंजे होकर जीने के बजाय मलेरिया से मर जाना बेहतर मानते है।

ऐसी विषम परिस्थितियों मे लड़कों को यही मशविरा दिया जा सकता है कि गंजे होने पर,उसकी नौबत सर पर सवार होते देख हाथ पाँव फुला लेना ठीक नहीं। सच्ची बात तो यह है कि खूब सारी देखभाल और खर्च करने के बावजूद इन बालो पर भरोसा करना नादानी है।बालों की चिंता छोड़ें ये चल उड़ जा रे पंछी टाईप की बेवफा चीज हैं जब तक मर्ज़ी होगी ये रहेंगे,जब साथ छोड़ना चाहेंगे आप लाख कोशिश करें ये चल ही देगें। इन्हें मनाने के लिये भाँति भाँति के शैम्पू,हेयर जैल आर्युवेदी दवाओं या गधी के दूध पर नगदी खर्च करना पानी मे पैसे फेंकने के बराबर है। इनसे बड़ा अहसानफरामोश कोई दूसरा नहीं। आप लाख मनुहार करते रहें इनकी, जब ये चल उड़ रा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना वाला गाना गाने के मूड मे आये तो उड़ ही जाना है इन्हें। ये बस नाराज़ फूफाजी वाले मोड मे आ जायेंगे लाख मनाइये इन्हें ये जाये बिना मानेंगे नहीं। इसलिये जाने दीजिये इन्हें, वैसे भी जाने वालो को कौन रोक पाया है ! जाने वाले चले ही जाते हैं। चार दिन रोना धोना होता है उसके बाद जिंदगी फिर अपने ढर्रे पर चल पड़ती है।

गंजा होने का दुख मनाने के बजाए इतिहास की किताबें टटोलिये। लिस्ट बनाईये उन लोगों की,जिन्होने बिना बाल के भी झंडे गाड़े हैं,नोट कमाये है ,कम्पनियाँ खड़ी की है,देशों पर राज किया है और मिस वल्डो के दूल्हे बने हैं।आप पायेगे ,दुनिया गंजों के ही क़ाबू मे है, लिहाज़ा मन छोटा ना करें। इन सफल खल्वाटो को अपना आदर्श बनायें। हौसला बनाए रखिए,मेरा भरोसा कीजिए,सर के सफ़ाचट मैदान पर ही धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि की देवी सरस्वती जुगलबंदी करना पसंद करती है और चंद अपवादों को छोड़ दें तो अब भी चाँद वालो को चाँद सी महबूबा मिलने की पूरी गुंजाइश है।

बाल मुसीबत है,ख़र्चे का घर है ये।ये हैं तो दुनिया के तमाम मँहगे शैम्पू,कंडीशनर डाका डालते है हमारी जेब पर। इन्हे सजाने सँवारने मे किया गयी ख़र्च,वह वक़्त जो इन पर बरबाद किया गया, ये सब हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता के सबसे बड़े दुश्मन है। गंजों को देखिए,सुबह मुँह धोना ही काफ़ी होता है उन्हें। बाल वाले, उनसे छुटकारा पाये बिना गंजे होने का फ़ायदा नहीं समझ सकते।

आप जिस बात के लिये बालों पर धन ख़र्च कर रहे है वह सिरे से ही गलत है। सारी छोरियाँ यदि केवल बालो को देख कर ही निहाल हो रही होती तो मेरी तरह तितर बितर बाल लिये फिर रहा शाहरूख खान सुपर स्टार ना होता। मैं माननीया अपरूपा सुंदरी वैजयन्ती माला जी से भी सहमत नहीं हूँ,मात्र जुल्फ़ों के उड़ने से ही कँवारियो का दिल नहीं भटक सकता।पूना वाली को छोड़ हमारे देश की कन्याये हमेशा से पर्याप्त समझदार है वे जानती है केवल जुल्फ़ों से घर नहीं चलता ना सर पर टोकनी भर बाल लिये फिर रहे लड़कों के साथ जिंदगी गुज़ारी जा सकती है। वे आपकी हैसियत भी देखती है और हैसियत खोपड़ी के अंदर सुरक्षित तेज़ दिमाग से हासिल होती है।

लड़कों को यही सलाह मेरी। बालों को लेकर मन न गिराएँ। अब भी ऐसी लड़कियों की तादाद ज़्यादा है जो लड़कों के बालों के बजाय दिमाग़ को तवज्जो देती है। मेरी बात मानिए। रोज़ सुबह उठकर भीगे बादाम खाइये। ताकि दिमाग़ मे तरावट बनी रहे।किताबों से वर्जिश करे इसकी। फिर देखिये बात बनेगी। और तितर बितर बालों के या बालों के बग़ैर भी बनेगी।

विचार

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं

श्रम की मृत्यु और चेतना के पुनर्जन्म का नया समय

कोई भी समाज अपने बच्चों को दंडित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। कानून से संघर्षरत बच्चों के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण अंतत: समाज के लिए ही विनाशकारी साबित होगा। किसी भी बच्चे के पुनर्वास में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किशोर न्याय अधिनियम में प्रयुक्त न्याय के उद्देश्य की अवधारणा की अधिनियम के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी उद्देश्य के अनुरूप समझा जाना चाहिए।

यह मानव इतिहास का सबसे अनूठा विरोधाभास है–जिस 'श्रम' से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य ने सदियों तक तकनीक का विकास किया, आज जब वह मुक्ति सामने खड़ी है, तो मनुष्य भयभीत है। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोट और स्वचालित मशीनें हमारे सारे उत्पादक, प्रशासनिक और तार्किक काम संभाल लेंगे, तब यह सवाल उठना लाजिमी है कि यदि जीवन में कुछ 'करना' ही नहीं बचेगा, तो मनुष्य होने का अर्थ क्या रह जाएगा? क्या हम एक अंतहीन ऊब (Existential Boredom) के दलदल में धंस जाएंगे, या यह युग मानव चेतना के एक नए, अधिक समृद्ध अध्याय की शुरुआत करेगा?

औद्योगिक क्रांति के बाद से मनुष्य की पहचान उसके काम से जुड़ गई– 'आप क्या करते हैं?' ही यह तय करता है कि 'आप कौन हैं।' जब मशीनें इस काम को छीन लेंगी, तो शुरुआत में एक गहरा शून्य और असंतोष पैदा होगा, क्योंकि हमने 'सफलता' और 'संतोष' को केवल उत्पादकता (Productivity) से जोड़ना सीख लिया है।

भविष्य में संभावित इस ऊब से निपटने के लिए मनुष्य को अपनी परिभाषा बदलनी होगी। जब 'पेट भरने का संघर्ष' समाप्त हो जाएगा, तब काम 'मजबूरी' न रहकर 'आत्म-अभिव्यक्ति' (Self-expression) का माध्यम बनेगा। ऐसा लगता है तब हमारे जीवन में कला की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी।फाइन आर्ट (चित्रकला, मूर्तिकला) जैसी प्रक्रियाएं मनुष्य को उत्पादकता के इस नए संकट से बचाएंगी। जब एक चित्रकार कैनवास पर रंग बिखेरता है, तो वह किसी बाजार के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के कोलाहल को शांत करने के लिए करता है। कला मनुष्य को 'उपभोक्ता' से वापस 'स्रष्टा' (Creator) बनाएगी। हमारे पूर्वजों की चट्टानों, पहाड़ों, शिलाओं को तराश कर बनाए मंदिरों, मूर्तियों में उस शिल्प कला के बारे में विचार करिए, कितने लंबे समय तक तत्कालीन मनुष्य इन कलाओं में अपने एकांत को सुख से भर देने का सफल प्रयास करता रहा होगा।

मशीनी युग में सबसे बड़ा खतरा शारीरिक और मानसिक जड़ता का होगा। जब उंगलियां केवल स्क्रीन छुएंगी और रोबोट सारा शारीरिक श्रम कर देंगे, तब मनुष्य अपने ही शरीर से कटने लगेगा। यहीं पर हमारी आदिम कलाएं– विशेषकर मार्शल आर्ट और परफॉर्मेंस आर्ट (नृत्य, थिएटर)–एक सुरक्षा कवच की तरह उभरेंगी।

कलारीपयट्टू, कुंग-फू या कराटे जैसी विधाएं केवल आत्मरक्षा के साधन नहीं हैं; ये मन और शरीर के गहरे अनुशासन की यात्रा हैं। मशीनों के दौर में, जब पसीना बहाने की कोई व्यावहारिक जरूरत नहीं होगी, तब मार्शल आर्ट और योगाभ्यास मनुष्य को उसकी शारीरिक सीमाओं, ताकत और आदिम प्रवृत्तियों से जोड़े रखेगा। यह उस 'अनचाही ऊब' को तोड़ने का सबसे प्रखर तरीका होगा।

डिजिटल और आभासी (Virtual) दुनिया के चरम पर होने के कारण लोग इंसानी स्पर्श और उपस्थिति के लिए तरसेंगे। थिएटर, लाइव म्यूजिक या नृत्य जैसी कलाएं 'उसी क्षण' (In the moment) जीने का अहसास कराती हैं। मशीनों के पास भूतकाल का डेटा है और भविष्य का प्रेडिक्शन, लेकिन 'वर्तमान क्षण' का जो उत्सव परफॉर्मेंस आर्ट में है, वह केवल मनुष्य ही महसूस और साझा कर सकता है।

हो सकता है एआई हर काम को परफेक्ट (त्रुटिहीन) तरीके से करने में सक्षम हो। वह एक आदर्श राग गा सकता है, बिना किसी व्याकरण की गलती के कहानी लिख सकता है और सटीक ज्यामितीय चित्र बना सकता है। लेकिन कला का सौंदर्य अक्सर उसकी 'कमियों' (Imperfections) में होता है। हाथ से बुने हुए कपड़े की असमान बुनावट में, या मिट्टी के घड़े पर कुम्हार की उंगलियों के टेढ़े-मेढ़े निशानों में जो मानवीय स्पर्श होता है, वह मशीन की गणितीय सटीकता में कभी नहीं मिल सकता।

भविष्य में, 'हैंडमेड' (Handmade) और 'ह्यूमन-मेड' (Human-made) दुनिया के सबसे महंगे लक्जरी ब्रांड बन जाएंगे। लोग मशीन के बनाए परफेक्ट संगीत के बजाय किसी इंसान की कांपती हुई, लेकिन भावनाओं से भरी आवाज सुनना पसंद करेंगे। यह कमियों का उत्सव ही मनुष्य को संतोष देगा। इतिहास गवाह है कि जब-जब मनुष्य अत्यधिक खाली समय से घिरा है, समाज में अवसाद या अराजकता बढ़ी है। यदि एआई युग में आदिम कलाओं को संस्थागत रूप से नहीं अपनाया गया, तो शायद मनुष्य आत्मघाती ऊब का शिकार भी हो सकता है।

इन सब संभावनाओं, आशंकाओं के चलते हमें अभी से जीवन में कला को केवल 'शौक' नहीं, बल्कि 'जीवन पद्धति' (Lifestyle) बनाना होगा। पुराने समय में कबीलों के अपने नृत्य होते थे, त्योहार होते थे और मार्शल आर्ट के अखाड़े, योग केंद्र होते थे, जो समाज को आपस में जोड़ते थे।भविष्य के समाज में ये आदिम प्रक्रियाएं नए 'अनुष्ठान' (Rituals) बनेंगी। लोग शाम को कम्युनिटी सेंटर्स में इकट्ठा होंगे–कोई मिट्टी को आकार दे रहा होगा, कोई तलवारबाजी सीख रहा होगा, तो कोई मंच पर कविता पाठ कर रहा होगा। यह साझा रचनात्मकता मनुष्यों को अकेलेपन और ऊब के अवसाद से बचाएगी।

कृत्रिम बुद्धिमता और रोबोटिक्स का आना मानव श्रम का अंत जरूर है, लेकिन यह मानवीय संवेदनाओं का अंत नहीं है। बल्कि, यह पहली बार मनुष्य को इस योग्य बनाएगा कि वह 'मशीन की तरह काम करना' बंद करे और 'मनुष्य की तरह जीना' शुरू करे।

जब पेट भरने और उत्तरजीविता (Survival) का संघर्ष मशीनें संभाल लेंगी, तब मनुष्य अपनी चेतना के उच्चतम शिखर की ओर बढ़ सकेगा। फाइन आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट और मार्शल आर्ट जैसी आदिम विधाएं मनोरंजन के साधन मात्र नहीं रहेंगी; वे उस युग में मनुष्य के 'मनुष्य बने रहने' की अनिवार्य शर्तें बन जाएंगी। तकनीक हमें सुविधा देगी, लेकिन संतोष और खुशी केवल हमारी आदिम रचनात्मकता ही दे पाएगी।

चिंतन

चंदन यादव

लेखक बाल साहित्यकार हैं।

अच्छा समाज 'सामान्यीकरण' से आगे है!

मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो 'सामान्यीकरण' की इस सीमा के शिकार हैं। मसलन, उन्हें एक मराठी भाषी मिले जो कंजूस भी हो तो वे दावे से कहने लगेंगे कि मराठी लोग कंजूस होते हैं। कोई किसी मशीन का एक नट खोल रहा हो, जो उससे नहीं खुल रहा तो वो तुरंत कहेंगे 'तुमसे तो 'कुछ' नहीं आता।' वो ये तो सोच ही नहीं पाएंगे कि हर आदमी के अनुभव, ज्ञान और कौशल के क्षेत्र अलग-अलग हो सकते हैं। अगर कोई शिक्षक इस तरह का सामान्यीकरण करता है तो उसकी कक्षा के बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बच्चों को लगेगा कि वे तैर सकते हैं, पेड़ पर चढ़ सकते हैं, पचास पेड़ों के नाम जानते हैं; पर इसका कोई महत्व नहीं है। अगर वे किताब का एक वाक्य नहीं पढ़ पाए तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ नहीं आता!

भाषा और जीवन में 'सामान्यीकरण' का बहुत उपयोग होता है। उदाहरण के लिए 'भिंडी' को हर गाँव में अलग-अलग नामों से बुलाया जाने लगेगा तो अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि किसकी बात हो रही है। भाषाओं में उसके हर शब्द के लिए यह बात लागू है कि उसका एक व्यापक सामान्य अर्थ है। सब लोग उस शब्द से वही अर्थ अर्जित करते हैं। तभी बातचीत और संवाद मुमकिन होते हैं। 'सामान्यीकरण' भाषा की ताकत है। पर सुनने-पढ़ने वाला किसी बात की गहराई में नहीं जाए तो यह भाषा की सीमा भी बन जाती है।

मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो 'सामान्यीकरण' की इस सीमा के शिकार हैं। मसलन, उन्हें एक मराठी भाषी मिले जो कंजूस भी हो तो वे दावे से कहने लगेंगे कि मराठी लोग कंजूस होते हैं। कोई किसी मशीन का एक नट खोल रहा हो, जो उससे नहीं खुल रहा तो वो तुरंत कहेंगे 'तुमसे तो 'कुछ' नहीं आता।' वो ये तो सोच ही नहीं पाएंगे कि हर आदमी के अनुभव, ज्ञान और कौशल के क्षेत्र अलग-अलग हो सकते हैं। अगर कोई शिक्षक इस तरह का सामान्यीकरण करता है तो उसकी कक्षा के बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बच्चों को लगेगा कि वे तैर सकते हैं, पेड़ पर चढ़ सकते हैं, पचास पेड़ों के नाम जानते हैं; पर इसका कोई महत्व नहीं है। अगर वे किताब का एक वाक्य नहीं पढ़ पाए तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ नहीं आता!

सामान्यीकरण एक कामचलाऊ कौशल है। बहुत से लोग यहीं तक सीमित रह जाते हैं। कोई बात सुन- पढ़ कर यह सोचना कि यह किसने कहा है? किस संदर्भ में कहा है? इसके पीछे किस तरह की सामाजिक राजनैतिक समझ काम कर रही है? क्या कहने वाले का इसमें कोई स्वार्थ है? श्रोता और पाठिका को सामान्यीकरण या सामान्य अर्थ ग्रहण से आगे ले जाने वाले प्रश्न हैं। जो इस तरह नहीं सोचती वह एक जड़ सामान्यीकरण से पीड़ित है।

मैं आज के सोशल मीडिया पर लोगों के विचार देखता हूँ तो समझ आता है कि यह कितनी विकराल समस्या है। 'राहुल गाँधी पप्पू हैं।' इसका सबसे व्यापक उदाहरण है। अगर यह सुनकर श्रोता और पाठकों ने सोचा होता कि यह किसने कहा है? किस संदर्भ में कहा है? इसके पीछे किस तरह की सामाजिक राजनैतिक समझ काम कर रही है? क्या कहने वाले का इसमें कोई स्वार्थ है? तो यह बात इस तरह बड़े पैमाने पर शायद ही प्रसारित प्रचारित होती! समाज में सांप्रदायिकता, अविश्वास, असहिष्णुता, नफरत और गैरजिम्मेदारी बढ़ने का कारण मुझे 'सामान्यीकरण' में भी दिखाई देता है।

'सामान्यीकरण' हमारी सोच, व्यवहार और पसंद नापसंद को भी नकारात्मक तरीके से पोषित और प्रभावित करता है।

हमें आज के बहुत से युवा भटके हुए नजर आते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हमारी शिक्षा में बच्चों को सामान्यीकरण से आगे ले जाने वाले तत्व नहीं हैं। प्राथमिक स्तर पर ऐसी कहानियों को बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता, जिनमें किसी तरह का द्वन्द्व हों। जो जीवन के उजले और सुंदर पक्षों के साथ कुरूपता और अँधेरे से भी परिचित कराये। बाद की कक्षाओं में इतिहास, समाज शास्त्र, दर्शन और साहित्य की पढ़ाई को कम बच्चे चुनते हैं। ये निसंदेह सोच को 'सामान्यीकरण' से आगे ले जाने वाले विषय हैं। पर रोजगारपरक नहीं होने के कारण उपेक्षित हैं। फलत; डिग्री तो मिल जाती है पर अपने समय, समाज और देश की समझ नहीं मिलती।

मुझे अच्छे साहित्य पर बहुत भरोसा है। वह पाठक को दूसरों के अनुभव, उनके जीवन, सोच विचार, और उलझन को महसूस कराता है। मैं पिछले दिनों दलित चिंतक ओमप्रकाश बाल्मीकि का एक लेख पढ़ रहा था। उन्होंने साहित्य के बारे में कहा है 'मेरे लिए पुस्तक का अर्थ है ऐसा अनुभव जगत जो जीने का हौसला देता है। संघर्ष के समय जूझने की जिजीविषा पैदा करता है। इर्द-गिर्द फैले सन्नाटे को तोड़ने में मदद करता है। अँधेरों में जुगनू की तरह टिमटिमाते गहन सरोकारों और वेदनाओं की रोशनी बन जाते हैं। और जीवन की बारीकियों, जटिलताओं को समझने में मददगार साबित होते हैं।

साहित्य की ये देन हमें भाषा के 'सामान्यीकरण' से आगे ले जाकर सोच विचार करने वाला जिम्मेदार और सचेत इंसान बनाती है।

ज़िंदगी का सामान्य कार्य व्यापार चलाने के लिए 'सामान्यीकरण' भी जरूरी है। पर सिर्फ इसी पर आश्रित होकर कोई भी संवेदनशील, उदार, सहिष्णु, समावेशी और विवेकशील भी हो सकेगा; इसमें मुझे संदेह है।

सामयिक

प्रयाग पाण्डे

लेखक नैनीताल निवासी स्तंभकार हैं।

अति पर्यटन चौपट न कर दे पर्यटन उद्योग

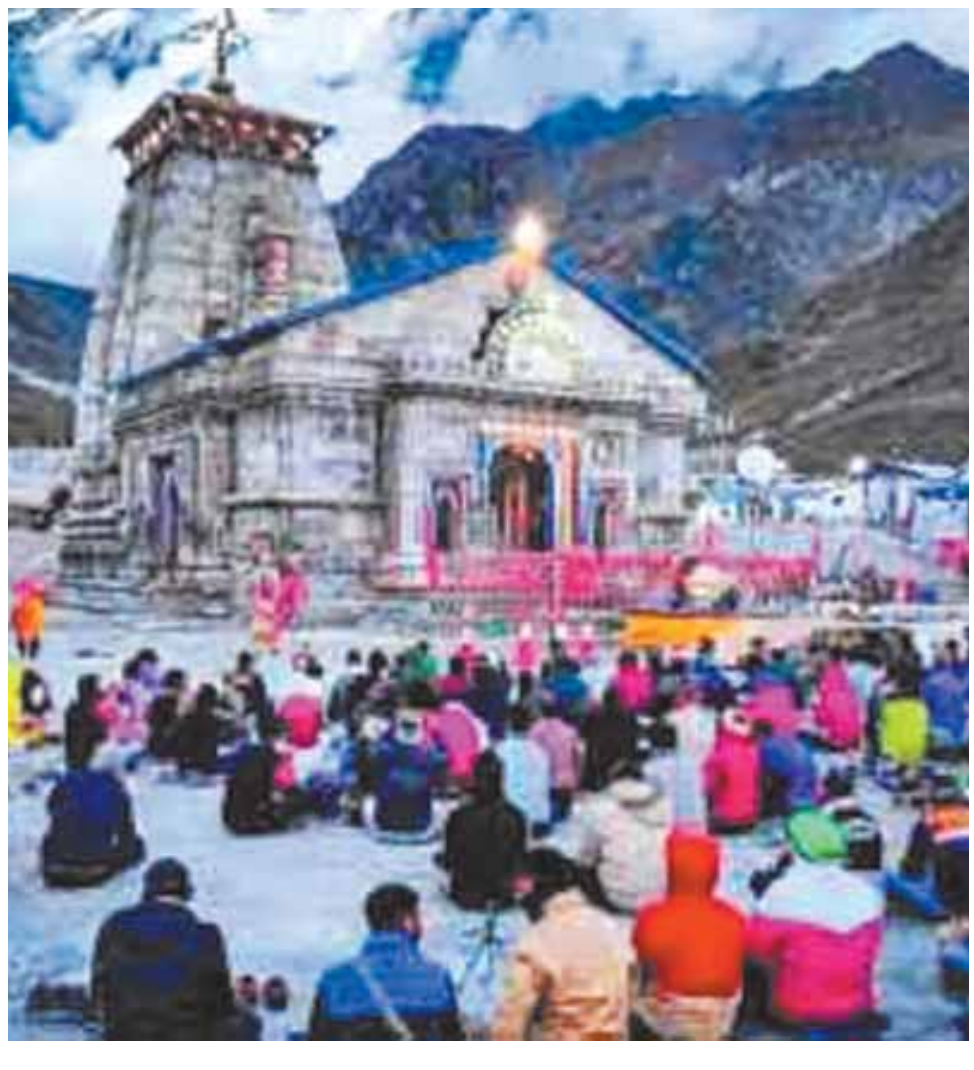

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता से अधिक पर्यटकों के आवागमन से मेहमान और मेजबान के बीच टकराव की घटनाओं में यकायक बढ़ोत्तरी हुई है। पहाड़ के पर्यटक स्थलों में आए दिन पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच छोटी - छोटी बातों पर लड़ाई - झगड़े, गाली - गलौच, मारपीट और हाथापाई जैसी अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं। अति पर्यटन के कारण उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं।

भारतीय संस्कृति में अतिथियों को बहुत महत्व दिया गया है। भारत की संस्कृति का प्राचीन सिद्धांत है- 'अतिथिदेवो भव।' इस कथन में अतिथि को देवताओं के तुल्य माना गया है। अतिथियों का देवता के रूप में सम्मान करने की सलाह दी गई है। आधुनिक पर्यटन के वर्तमान दौर में अनियंत्रित, अनियोजित एवं असंयोजित अति जन पर्यटन ने भारतीय संस्कृति के इस प्राचीन सिद्धांत को अप्रासंगिक बना दिया है। पर्यटक स्थलों की क्षमता से कई गुना अधिक भीड़, घोर बाजारवाद और उपभोक्तावाद ने अतिथि और आतिथ्यकर्ता के मैत्रीपूर्ण व्यवहार में खटास घोल दी है। दोनों के मध्य का सौहार्द गड़बड़ा गया है।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता से अधिक पर्यटकों के आवागमन से मेहमान और मेजबान के बीच टकराव की घटनाओं में यकायक बढ़ोत्तरी हुई है। पहाड़ के पर्यटक स्थलों में आए दिन पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच छोटी - छोटी बातों पर लड़ाई - झगड़े, गाली - गलौच, मारपीट और हाथापाई जैसी अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं। अति पर्यटन के कारण उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं।

पर्यटन कुप्रबंधन के कारण उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में पचाने की क्षमता नहीं रह गई है। अनियंत्रित पर्यटन ने पहाड़ के आधारभूत सुविधाओं के ढांचे को चरमरा दिया है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आवागमन से पहाड़ की अधिकांश मोटर सड़कें दोपहिया और चौपहिया वाहनों से पट गई हैं। लोगों को घंटों सड़क जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पहाड़ में एक घंटे के सफ़र में दस घंटे लग रहे हैं। गाड़ियों की भीड़ और जाम से समूचा पहाड़ त्रस्त है। स्थानीय निवासियों की दैनंदिन की गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। अति जन पर्यटन से पहाड़ में भौतिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। वहन क्षमता से अधिक पर्यटकों के आने से मेजबान और मेहमान के बीच टकराव बढ़ा है।

उत्तराखंड में पर्यटन प्रबंध की माँग और आपूर्ति में सामंजस्य बैठाए बगैर अनियंत्रित पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि यहाँ स्थानीय संसाधनों के अनुसार भीड़ स्थानीय लोगों के लिए भौतिक एवं सामाजिक बोझ न बने इसके लिए पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता के आधार पर पर्यटकों की संख्या को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। अति पर्यटन से स्थानीय लोगों के मन में पर्यटकों के प्रति विद्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है, यह स्थिति पर्यटन उद्यम के लिए हितकर नहीं है। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता और उनकी व्यावसायिक उपयोगिता को बनाए रखने के लिए पर्यटकों की संख्या सुनिश्चित करना आवश्यक है। स्थानीय सही प्रबंधन और नियोजित पर्यटन की आवश्यकता है। जब स्थानीय निवासियों के लिए चलने को सड़क - रास्ते न बचें, बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो और स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को नजरअंदाज कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो स्थानीय लोगों के मन में पर्यटकों के प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न होने की आशंका बन जाती है। पर्यटन के इस अनियोजित विकास में स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं की सरासर अनदेखी की जा रही है।

सुनियोजित पर्यटन व्यवस्था के लिए स्थानीय क्षमताओं की समझ होना जरूरी है। पर्यटकों की अति निवासियों से मधुर संबंध और सहयोग से ही पर्यटन उद्योग को टिकाऊ और दीर्घजीवी बनाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का सहयोग तभी मिलेगा जब पर्यटन से उनके रोजमर्रा के कामों में व्यवधान उत्पन्न न हो और उन्हें पर्यटन से आर्थिक लाभ प्राप्त हो। उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को दीर्घकालिक बनाना है तो अनियंत्रित पर्यटन पर प्रभावी अंकुश लगाने और पर्यटन गतिविधियों को सीधे स्थानीय लोगों की आजीविका से जोड़ने की आवश्यकता है। इसके बगैर मेजबान और मेहमान के बीच सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण रिश्ते कायम नहीं हो सकते हैं।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज
लेखक स्तम्भकार हैं।

कौन किसके संपर्क में है ?

वैसे तो हर किसी क्षेत्र में यह बात काफी मायने रखती है कि कौन किसके संपर्क में है ? क्योंकि ऐसा कहा और माना जाता है कि आदमी जब किसी के साथ संगत करता है तो उसका रंग उस पर चढ़े बिना नहीं रहता। अब यदि जिंदगी में कोई सुनहरा अवसर मिल जाने का योग बन जाएं, तो कोई-कोई बिरले ही ऐसे होते हैं जो अपनी निष्ठा और समर्पण भाव को विशुद्ध रूप से अक्षुण्ण रख पाते हैं। अन्यथा सुना है कि आजकल हर ईमान की कीमत हुआ करती है लेकिन जो ईमान किसी कीमत पर नहीं बिकता, बहुत संभव है कि उसकी पर्याप्त कीमत नहीं लग पाई हो। जिसके चलते ईमान का ईमान बना हुआ है।

हालांकि मैं समझता हूं कि शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन फिर भी जमाने के दस्तूर को देखकर ऐसा भी लगता है कि शायद मैंने गलत नहीं सुना होगा। लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत कुछ संभावना इस बात की होती है कि आदमी की जिंदगी में कभी-कभी कमजोर पल भी आ जाते हैं। जिसके चलते आदमी अपने निष्ठा और समर्पण भाव को ताक पर रख दिया करता है। वैसे भी सियासत में रहकर जमाने भर की उठापटक और भागदौड़ करते हुए अंतर्मन के कोने-कोने में यह भाव विद्यमान होता ही है कि ऐसे-वैसे या चाहे जैसे-तैसे बस एक बार सत्ता की चाबी हाथ लग जाएं।

हालांकि इस भाव को कोई जाहिर नहीं करता लेकिन सियासत में आदमी का हाव-भाव और व्यवहार चींख-चींख कर इसी तथ्य की गवाही देता है कि वादे चाहे जो किए जाएं, नारे चाहे जो लगाए जाएं, लेकिन आजकल के दौर में राजनीति भी निवेश करने का और तगड़ा लाभ प्राप्त करने का एक आसान सा जरिया हो गई है। बस जरूरत इस बात की हुआ करती है कि आप सामने आए अवसर को पहचाने। वैसे भी जिंदगी में सुनहरे अवसर बार-बार नहीं मिला करते। दरअसल जन्म-जन्मांतर के शुभ कर्म उदय में आने पर ही ऐसी कोई संभावना बनती है कि हमारे अपने मत की कीमत हमारी मुंह मांगी मुराद को पूरा कर सकती हो।

यह तथ्य जग जाहिर है कि जब दो खरबूजे आमने-सामने हो तो खरबूजे का खरबूजे को देखकर रंग बदलना बहुत हद तक स्वाभाविक हो जाता है। आजकल संपर्क के लिए संचार माध्यम इतने विकसित हो चुके हैं कि आदमी चाहे तो मजे से निहायत ही एकांत के पलों में भी दीन दुनिया की खबर रखते हुए दुनिया के किसी भी कोने में बैठी शख्सियत से अपना संपर्क स्थापित कर सकता है। दरअसल संपर्क तो निजी पसंद के आधार पर तय होता है लेकिन कभी-कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है कि किसी एक का दूजे से संपर्क करना उसके अपने व्यापक हित में समय की मांग बन जाता है। एक प्रकार से इसे 'धंधे के सीजन' के रूप में भी देखा जा सकता है।

वैसे ऐसे अवसर हर किसी के लिए कोई बार-बार नहीं आते। यही कारण है कि आमतौर पर गर्म लोहे पर चोट कर दी जाती है और सामने वाले की हैसियत और महत्व को अपने खाते में जमा कर लिया जाता है। अब यह जो धंधे का सीजन है, इसका लाभ लेने वाले तात्कालिक रूप से तो लाभान्वित होते ही हैं लेकिन उन्हें इसका दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होने की भी प्रबल संभावनाएं रहा करती है। सियासी जगत में कभी-कभी यह प्रश्न काफी अहम हो जाता है कि कब, कौन, कहां और किससे संपर्क स्थापित कर सकता है। ऐसे में अपने कुनबे की साख बचाने और कायम रखने के लिए सियासत की शतरंजी बाजी के प्यादों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रखना आवश्यक हो जाता है।

ऐसी स्थिति में उनके लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश रहा करती है। आमतौर पर यह वह स्थान होता है जहां संबंधित दल की हुकूमत चलती हो। इसके लिए अपनी हुकूमत वाले राज्य में सर्व सुविधा युक्त रिसोर्ट से भला और कौन सा अच्छा स्थान हो सकता है। वैसे अपने खेमे के समूह को ठहरने को तो होटल में भी ठहराया सकता है लेकिन ऐसा करने पर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि निहायत ही एकांत के पलों मे कब, कोई किससे संपर्क कर लेवे। बड़ी अजीब बात है कि सियासत में कभी-कभी ऐसा अवसर भी आता है जब अपने ही बंदों को एक प्रकार से बंधक बनाया जा सकता हो।

97वीं ऑपरेशन एंड को-ऑर्डिनेशन कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक संपन्न

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सोमवार को भोपाल में 97वीं ऑपरेशन एंड को-ऑर्डिनेशन कमेटी (OCC) की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान राज्य विद्युत ग्रिड के सुरक्षित, विश्वसनीय एवं समन्वित संचालन, विद्युत मांग-आपूर्ति प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी एकीकरण, ग्रिड अनुशासन, ट्रांसमिशन समन्वय तथा मध्य प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही विभिन्न परिचालन संबंधी मुद्दों पर उपयोगी सुझाव एवं निर्णय लिए गए, जिनसे प्रदेश की विद्युत प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं दक्ष बनाने में सहायता मिलेगी ।

स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के मुख्य अभियंता श्री प्रदीप सचान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक (वाणिज्य एवं तकनीकी) श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) डॉ. राकेश शर्मा, उप मुख्य महाप्रबंधक (संचालन एवं संधारण) श्री शिशिर गुप्ता, महाप्रबंधक (ऑपरेशन) श्री संजीव कुमार कुशवाहा, सहायक अभियंता श्री स्वप्निल खम्पारिया, उप महाप्रबंधक भोपाल दक्षिण शहर संभाग श्री राकेश त्रिपाठी, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज द्विवेदी, सहायक अभियंता श्री ऋषि तिवारी सहित एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी एमपी पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी एमपी पॉवर जनरेटिंग कंपनी, प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPP), अडाणी पॉवर, मेघा इंजीनियरिंग, रेलवे तथा विद्युत क्षेत्र से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर बैठक की कार्यवाही का संचालन ऑपरेशन एंड को-ऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी श्री विवेक कुमार अग्रवाल ने एवं कार्यक्रम संचालन महाप्रबंधक (संचालन एवं संधारण) श्री संजीव कुशवाहा एवं सहायक अभियंता सिविल सुश्री हिमांशी पांडे ने किया। बैठक के सफल आयोजन पर सभी सहभागी संस्थाओं ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं एवं समुचित समन्वय की सराहना की ।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने 97वीं ऑपरेशन एंड को-ऑर्डिनेशन कमेटी (OCC) की बैठक के सफल आयोजन पर कहा कि प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। ग्रिड स्थिरता को बनाए रखना और आधुनिक तकनीकों का बेहतर क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी विद्युत उपक्रमों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उपभोक्ता हितों की रक्षा और ग्रिड की सुरक्षा के लिए सभी बिजली कंपनियों को मिलकर प्रयास करने होंगे, जिससे आने वाले समय में परिचालन दक्षता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

58 गांवों के आंशिक हिस्सों को शामिल करने की तैयारी

शहर को नगर निगम बनाए जाने की कवायद तेज

एस. द्विवेदी, बैतूल। बैतूल शहर को नगर पालिका से नगर निगम बनाए जाने की कवायद तेज हो गई है। नगर निगम के गठन के लिए शहर के 10 किलोमीटर दायरे में आने वाली 29 ग्राम पंचायतों के 58 गांवों के आंशिक हिस्सों को शामिल करने की योजना तैयार की गई है। क्योंकि निगम बनाने के लिए करीबन तीन लाख की आबादी होना आवश्यक है, जबकि अभी शहर की आबादी करीब डेढ़ लाख के आसपास ही है। बैतूल शहर के आसपास के गांव और पंचायते तथा नगर परिषद बैतूलबाजार का क्षेत्र एवं बालाजीपुरम, यदि बैतूल शहर में जुड़ जायेंगे, तो मापदंड के अनुरूप आबादी हो जायेगी। फिर प्रस्ताव पारित होने के बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र, दावे-आपत्तियों के निराकरण और शासन को अंतिम प्रस्ताव भेजने जैसी लंबी प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें कुछ वर्षों का समय लग सकता है। उधर, प्रशासन और जनप्रतिनिधि स्तर पर भी शहर को निगम बनाने की तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। विगत दिनों विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कलेक्ट्रेट में एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी, जिसमें नगर निगम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई थी। विधायक हेमंत खंडेलवाल लगातार इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दे रहे हैं। जिससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि बैतूल को नगर निगम का दर्जा देने की दिशा में गंभीर और तेज प्रयास किए जा रहे हैं।

नगर निगम के अनुरूप विकास कार्यो पर काम शुरू- नगर पालिका द्वारा नगर निगम के अनुरूप शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कई विकास कार्यों पर भी काम शुरू कर दिया गया है। इनमें बस स्टैंड शिफ्टिंग, अंडरब्रिज निर्माण, सब्जी एवं फल बाजार, आईएसबीटी, नई मंडी, अभिनंदन सरोवर कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट स्टेडियम, फायर स्टेशन और पार्क जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा गीता भवन के लिए भूमि आवंटन, स्ट्रीट स्ट्रीट फूड जोन, फूड कोर्ट और मल्टीलेवल गतिविधियों की योजना पर भी काम चल रहा है। वहीं ताप्ती बैराज पर इंटेकवेल निर्माण, 22 किलोमीटर पाइपलाइन विस्तार और बैराज मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा कर, इन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम बनने की यह प्रक्रिया यदि योजनानुसार आगे बढ़ती है तो आने वाले वर्षों में बैतूल शहर के विकास की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

निगम बनने पर 58 गांव हो सकते हैं शामिल

बैतूल से लगी 29 ग्राम पंचायतों के 58 गांवों के आंशिक हिस्सों को शामिल करने की योजना तैयार की गई है। इन पंचायतों में कढ़ाई, दनोरा, बडोरा, आरूल, बाजपुर, भैंसदेही, खेड़ली, मरामझिरी, टेमनी, जामठी, खेड़ला, डहरगांव, खेड़ीसांवलीगढ़, महदगांव, भदूस, कुम्हारटेक, भोगीतेड़ा, रोढ़ा, सूरगांव, भरकावाड़ी, खंडारा, मलकापुर, मिलानपुर, बयावाड़ी, ढोढवाडा और खडला सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद अगली प्रक्रिया के तहत सभी संबंधित 29 ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिए जाएंगे। इसके बाद प्रस्ताव का प्रकाशन किया जाएगा और दावे-आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। वहीं नगर पंचायत बैतूलबाजार का क्षेत्र भी इसमें शामिल करने की योजना है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में लगभग दो से तीन वर्ष का समय लग सकता है।

गांवों का हो रहा नगरीकरण

जानकारों का कहना है कि शहर के आसपास स्थित गांवों का वैसे भी नगरीकरण हो रहा है। इन क्षेत्रों में नई-नई कॉलोनियां बन चुकी है। इसके साथ ही लोग भी कृषि पर आश्रित न रहकर रोजगार व आजीविका के लिए अन्य कार्यों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नगर निगम में गांवों को शामिल करने के लिए भी यही एक प्रमुख शर्त रहती है कि उस गांव की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहे और वह क्षेत्र संक्रमणशील हो, जहां पर नगरों की तरह विकास हो चुका हो या हो रहा हो। परिषद में प्रस्ताव पारित होने के बाद बाद ही नगर निगम बनाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी। अभी से यह प्रक्रिया इसलिए प्रारंभ कर दी है, क्योंकि इसे पूरी होने में लंबा समय लग जाता है।

इनका कहना है

बैतूल नगर पालिका परिषद की बैठक में नगर निगम बनाए जाने के प्रस्ताव को शामिल किया गया था और परिषद में प्रस्ताव पास भी होकर शासन को भेजा जा चुका है। लगभग 15 दिन पूर्व विधायक महोदय एवं कलेक्टर सर को उक्त संबंध में मैप सहित प्रेजेंटेशन देकर पूरी जानकारी दी गई थी। विगत 15 दिनों में जनपद से हमने संबंधित गांवों का डाटा उपलब्ध करवा लिया है जिसमें इन गांवों को मिलाकर जनसंख्या लगभग 215000 हो रही है तथा लगभग 90000 की जनसंख्या को हमने फ्लोटिंग लिया है, जो बालाजीपुरम तथा अन्य टूरिस्ट स्थलों को देखते हुए लिया है, अब आगे की प्रक्रिया शासन द्वारा शुरू की जायेगी।

– नवनीत पांडे,
सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

गिद्ध और गौरैया के बाद अब बगुलों की घटती संख्या बढ़ा रही चिंता, बिगड़ते इकोसिस्टम के संकेत

प्राकृतिक सौंदर्य की प्रतिमा कहे जाने वाले मुलताई का बदलता पर्यावरणीय स्वरूप

बैतूल/ मुलताई। सतपुड़ा की मनमोहक वादियों में बसा मुलताई क्षेत्र कभी प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीवों-पक्षियों की विविध प्रजातियों के लिए देशभर में पहचान रखता था। यहां के घने वन, नदियां, तालाब, कुएं और जलाशय अनेक पक्षियों का प्राकृतिक आवास हुआ करते थे। लेकिन बदलते पर्यावरणीय हालात, अंधाधुंध प्राकृतिक दोहन और बढ़ते प्रदूषण के कारण अब इस क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन (इकोसिस्टम) लगातार बिगड़ता जा रहा है। गिद्ध और गौरैया जैसी पक्षी प्रजातियों के बाद अब सफेद बगुलों की लगातार घटती संख्या भी पर्यावरण प्रेमियों और विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। कभी ताप्ती सरोवर, नदियों, तालाबों और बांधों के किनारे स्थित ऊंचे वृक्षों पर सैकड़ों की संख्या में दिखाई देने वाले बगुलों के झुंड अब गिनेचुने ही नजर आते हैं। पहले आसमान में उड़ते सफेद बगुलों के समूह बच्चों के लिए कौतूहल का विषय हुआ करते थे, लेकिन आज उनका दिखना भी दुर्लभ होता जा रहा है।

बदलते पर्यावरण ने तोड़ी प्रकृति की कड़ियां

बुजुर्ग बताते हैं कि मुलताई क्षेत्र की हरियाली, प्रचुर जलस्रोत और प्राकृतिक वातावरण के कारण यहां बगुलों सहित अनेक पक्षियों की भरमार रहती थी। क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, नाले, तालाब और कुएं पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय और भोजन का प्रमुख स्रोत थे। समय के साथ जलस्रोत सिकुड़ते गए, हरित क्षेत्र कम होता गया और प्राकृतिक आवास नष्ट होने लगे। इसका सीधा प्रभाव पक्षियों की संख्या पर पड़ा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बगुले दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी संख्या पहले की तुलना में बहुत कम रह गई है।

प्राकृतिक दोहन के परिणाम अब स्पष्ट दिखाई देने लगे

समुद्र तल से लगभग 765 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुलताई, पचमढ़ी के बाद प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में शामिल है। कभी यह क्षेत्र अपने सुहावने मौसम के कारण राजा-महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थली माना जाता था। लेकिन पिछले दो दशकों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, फलदार वृक्षों का समाप्त होना, अवैध उत्खनन और अनियोजित विकास ने यहां के पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित किया है। इसका असर बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आ रहा है, जिससे किसान भी प्रभावित हो रहे हैं।

इनका कहना

कृषि में रासायनिक कीटनाशकों और दवाइयों का बढ़ता उपयोग केवल मानव स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि पक्षियों और अन्य जीव-जंतुओं के लिए भी घातक साबित हो रहा है। खेतों में मिलने वाले कीट जहरीले रसायनों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें खाने वाले पक्षियों के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बगुलों सहित कई पक्षी प्रजातियों की संख्या लगातार घट रही है।

.....आर.के. मालवीय, पर्यावरणविद् एवं प्रभारी प्राचार्य सांदीपनि विद्यालय बैतूलबाजार

किसानों के सच्चे साथी हैं बगुले

ग्राम ताईखेड़ा और चंदोरा के बीच स्थित एक खेत में धनिया की फसल की निराई कर रही महिला के आसपास बड़ी संख्या में बगुले भोजन तलाशते दिखाई दिए। स्थानीय ग्रामीण राहुल नरवरे बताते हैं कि बगुले फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि खेत में मौजूद हानिकारक कीटों को खाकर किसानों की मदद करते हैं। बुवाई के समय भी यह किसानों के साथ चलते हैं और बीज खाने के बजाय फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का शिकार करते हैं। ग्रामीण पृथ्वी पवार का कहना है कि खेतों में नियमित रूप से काम करने वाले किसानों को बगुले पहचानने लगते हैं। किसान के साथ-साथ चलते हुए वे मिट्टी में छिपे कीटों को निकालकर खाते रहते हैं। किसानों द्वारा उन्हें भगाने का प्रयास करने पर भी वे अधिक दूर नहीं जाते। यह दृश्य मानव और प्रकृति के बीच वर्षों पुराने विश्वास और सह-अस्तित्व के संबंध को दर्शाता है। हालांकि, पहले जहां ऐसे बगुलों के बड़े-बड़े झुंड दिखाई देते थे, अब उनकी संख्या लगातार घट रही है।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते जलस्रोतों का संरक्षण, वनों का संवर्धन, रासायनिक दवाइयों का संतुलित उपयोग और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के प्रभावी प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाले वर्षों में बगुलों सहित अनेक पक्षी प्रजातियां भी इस क्षेत्र से पूरी तरह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकती हैं। प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर गंभीर प्रयास करने होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव राजगढ़ जिले के 352 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण

मुख्यमंत्री मंगलवार को भैंसवामाता में करेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 30 जून को जिले के विकासखंड सारंगपुर अंतर्गत भैंसवामाता जी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर राजगढ़ जिले के 352 करोड रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल, सांसद श्री रोडमल नागर भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर 1:45 बजे भैंसवामाता पहुंचकर दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद दूध तलैया में गंगा पूजन, गौ-पूजन एवं पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 की प्रदर्शनी का अवलोकन कर जिले में संचालित जल संरक्षण एवं पर्यावरणीय नवाचारों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री टेटवाल, सांसद श्री नागर एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल भी उपस्थित रहेंगे तथा अपने विचार व्यक्त करेंगे। राजगढ़ जिले की पर्यटन फिल्म, कॉफी टेबल बुक एवं सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया जाएगा। साथ ही जिले में कराए गए विकास कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, जल संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ भी वितरित किए जाएंगे।

जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ उनके संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 का गरिमामय समापन होने जा रहा है। अभियान की इस अल्पावधि में ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये गये हैं। इस महा-अभियान ने पूरे प्रदेश में भू-जल संवर्धन, जल गुणवत्ता परीक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नदी पुनर्जीवन और जन-जागरूकता की एक नई चेतना जागृत की है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे सतलोक आश्रम

तीन दिवसीय महा समागम का हुआ समापन

बैतूल। सतलोक आश्रम में कबीर साहेब के 629 में प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल महाराज के सानिध्य में चल रहे विशाल तीन दिवसीय समागम कार्यक्रम का समापन भोग कि वाणी के साथ तरीके से हुआ। इस सामाजिक कार्यक्रम के तीसरे दिन मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व पूर्व कैबिनेट मंत्री व प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे, कांग्रेस कमेटी बैतूल के जिला अध्यक्ष निलय डागा, मप्र कर्मचारी प्रकोष्ठ के कार्यवाहक अध्यक्ष अरुण गोठी, कांग्रेस कमेटी बैतूल के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत वागद्रे, नवनीत मालवी एवं कई जनप्रतिनिधि आश्रम में पधारे और संत रामपाल महाराज द्वारा किए जा रहे ऐसे जनकल्याण के कार्यक्रमों को देखकर भूरी भूरी प्रशंसा की। जीतू पटवारी ने संत रामपाल महाराज को सच्चे समाज सुधारक के रूप में बताया और उनके द्वारा किए जा रहे समाज सुधार के कार्य को देखकर बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे समाज सुधार के कार्यक्रम में हमेशा आता रहूंगा। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हुआ और सभी ने शांतिपूर्वक भंडारा प्रसादी ग्रहण की।

तबादलों का 'बाजार', एजेंट का 'दरबार'

प्रदेश में बीते दिनों तबादलों का 'सीजन' अपने पूरे शबाब रहा। राजस्व विभाग में तो पटवारियों के तबादले किसी 'शेयर बाजार' की तरह हो गए हैं–सुबह लिस्ट आती है, और शाम होते-होते उसका 'सुधार' (सौदा) हो जाता है। सुनने में आया है कि एक बड़े जिले में चार दर्जन पटवारियों को इधर-उधर किया

मोहन का मंत्रालय
आशीष चौधरी

गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही आदेशों में ऐसी 'कांट-छांट' हुई कि जैसे तबादला नहीं, कोई कच्ची पर्ची हो। इस पूरे खेल के सूत्रधार एक 'जनप्रतिनिधि' और उनके वफादार 'एजेंट' बताए जा रहे हैं। सुना है कि 2 से 5 लाख रुपये तक की 'कमीशनखोरी' के बाद पोस्टिंग का गणित सुलझाया गया। मंत्री जी ने तो तबादला नीति का पालन किया, पर जनप्रतिनिधि साहब का 'प्रभाव' नीति पर भारी पड़ गया।

बदले तेवरों से अफसरों की बढ़ी 'धड़कनें'

मंत्रालय में इन दिनों 'बड़े साहब' का बदला मिजाज चर्चा का हॉट टॉपिक है। कभी संतुलित रहने वाले साहब अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठकों में ऐसे 'अग्निबाण' छोड़ रहे हैं कि फील्ड के अफसरों के चेहरे का रंग उड़ना लाजिमी है। साहब की 'डिजिटल नजर' इतनी पैनी है कि स्क्रीन के उस पार बैठे अधिकारी का नर्वस होना ही उनकी तैयारी की पोल खोल देता है। उनकी तिरछी नजर का शिकार हुए अफसरों की सूची रोज लंबी होती जा रही है। अब गलियारों में इसके पीछे का गणित लगाया जा रहा है। जानकारों का तर्क है–अगर विदाई तय होती, तो मिजाज नरम होता। पर जिस तरह साहब की सख्ती लगातार 'अपग्रेड' हो रही है, उसने उनके कार्यकाल में 'एक्सटेंशन' की नई चर्चाओं को हवा दे दी है। फिलहाल, अफसर फाइलों से ज्यादा अपनी धड़कनों को संभालने में व्यस्त हैं!

आईएएस का 'एआई' प्रेम तकनीक या मुसीबत?

मंत्रालय में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इन दिनों 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' के कुछ ज्यादा ही प्रेम में हैं। निर्देश देने से लेकर दस्तावेजों का खाका तैयार करने तक, सब कुछ 'रोबोटिक' हो रहा है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में एआई के भरोसे प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें ऐसी चूक हुई कि मंत्री जी का पारा सातवें आसमान पर पहुँच गया। अब देखना यह है कि मंत्री जी की फटकार के बाद साहब का यह 'एआई-मोह' कम होता है या वे अभी भी मशीनी बुद्धिमानी के भरोसे ही 'मंत्रालय' चलाएंगे।

कांग्रेस का 'आत्मघाती' गोल

कांग्रेस के खेमे में इन दिनों हाथ में आए मुद्दों को खुद ही 'हवा' करने का अनोखा कौशल देखा जा रहा है। राज्यसभा प्रत्याशी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक न्यास की जमीन का मुद्दा गरमाया। प्रदेश मुखिया ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका, तो लगा कि कुछ बड़ा होगा। लेकिन, कुछ ही दिनों में पार्टी के एक कद्दावर नेता ने मुखिया के दावों को 'हवा-हवाई' बताकर अपनी ही पार्टी के अभियान को 'टाटा-बाय-बाय' कह दिया। कांग्रेस के लिए मुद्दा अब मुद्दा नहीं, बल्कि आपसी खींचतान का 'नजारा' बन गया है।

'सेटिंग' वाले असिस्टेंट कमिश्नर

प्रदेश के एक 'कमाऊ' विभाग में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर के जलवे इन दिनों किसी रसूखदार नेता से कम नहीं हैं। पिछली गड़बड़ियों पर हाल ही नोटिस मिला, तो साहब ने बड़ी मासूमियत से कहा, 'सब सेट हो जाएगा।' उनका 'सेट' होने का दावा भी मजबूत है, क्योंकि राजधानी आते ही वे मंत्रालय के एक विशेष फ्लोर पर अपनी हाजिरी लगाने जो जाते हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि प्रदेश के कई जिले की पूरी टीम उनकी 'इच्छा' से तैनात है। जिसे सरकार 'मलाईदार' विभाग कहती है, वहां साहब का 'राज' वाकई देखने लायक है।

पांढुर्णा के मोहिघाट में कुछ मिनट के अंतराल में दो बसें दुर्घटनाग्रस्त

22 से ज्यादा यात्री घायल, 6 गंभीर नागपुर रेफर

छिंदवाड़ा (नप्र)। एमपी के छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा में मोहि घाट पर सोमवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। घाट के खतरनाक मोड़ और ढलान पर कुछ ही मिनटों के अंतराल में दो यात्री बसें एक के बाद एक दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। हादसे में 22 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें से 15 से ज्यादा लोग बसों के भीतर फंस गए थे। गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार दोनों बसें भोपाल और इंदौर से यात्रियों को लेकर पांढुर्णा की ओर आ रही थीं। सुबह के समय लगातार बारिश होने और सड़क पर फिसलन के बीच मोहि घाट के ढलान वाले हिस्से में हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

मदद को दौड़े, बसों के शीशे तोड़कर निकाले गए यात्री– हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों, स्थानीय ग्रामीणों और पांढुर्णा पुलिस ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। कई यात्री बसों के भीतर फंस गए थे। स्थानीय

लोगों ने साहस दिखाते हुए बसों के शीशे तोड़े और दरवाजे खोलकर यात्रियों को बाहर निकाला। पुलिस और बचाव दल के पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई।

यात्रियों को हाथ-पैर और सिर में आई गंभीर चोटें– घायलों को एंबुलेंस और अन्य निजी वाहनों की मदद से पांढुर्णा के सिविल अस्पताल सहित आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार कई यात्रियों के सिर, हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार जारी है। फिलहाल किसी यात्री की मौत की सूचना नहीं है, लेकिन कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

हादसे में घायल हुए यात्री अशफाक खुर्शीद ने घटना के खौफनाक मंजर को बयां करते हुए बताया कि, सुबह तेज बारिश हो रही थी और मोहि घाट की सड़क पर ऑयल फैला हुआ था। मोड़ और ढलान पर जैसे ही बस आई, वह बुरी तरह फिसलने लगी। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, लेकिन गाड़ी पर से नियंत्रण पूरी तरह खो चुका था और देखते ही देखते चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना के बाद मोहि घाट मार्ग पर दोनों क्षतिग्रस्त बसों के आड़े-तिरछे खड़े होने के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। इसके बाद प्रशासन ने भारी क्रेन बुलाई और बसों को सड़क से किनारे किया, जिसके बाद रास्ता बहाल हो सका।

मोहन सरकार का ऐतिहासिक कदम

एमपी में दिव्यांगजन के लिए शुरू हुई 'राज्य निधि' योजना

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उनकी प्रतिभा को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 'राज्य दिव्यांगजन निधि' के संचालन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इस योजना के धरातल पर आने से अब खेल, कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में देश-दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले दिव्यांगों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

क्यों पड़ी इस निधि की जरूरत?

पिछले लंबे समय से आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय में ऐसे प्रतिभावान दिव्यांगजनों के आवेदन आ रहे थे, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं, लेकिन एक व्यवस्थित आर्थिक तंत्र (मैकेनिज्म) न होने के कारण उन्हें सहायता के लिए जिला और राजधानी के चक्कर काटने पड़ते थे। इसे देखते हुए फरवरी-मार्च में विभागीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन और प्रमुख सचिव सोनाली पोक्षे वायंगणकर व आयुक्त केजी तिवारी के प्रयासों से इस निधि का पूरा रोडमैप तैयार किया गया।

भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल : मंत्री नड्डा

मध्यप्रदेश को पीएम-केयर्स के तहत आधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरणों की सौगात

भोपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आयोजित 'डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स लॉन्च कार्यक्रम' में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। शुभारंभ की गई प्रमुख पहलों में आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान ऐप, आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैटबॉट, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (एनएचसीएक्स), यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (यूएचआई), ई-सुश्रुत क्लिनिक, ड्रग रजिस्ट्री, कॉमन LOINC कोड्स फॉर इंडिया (सीएलसीआई) तथा भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस (बीएचटीएस) शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा

ने कहा कि 90 करोड़ से अधिक आभा खाते और 100 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनने के साथ भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु 2.0 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों सहित सभी आयु वर्ग के नागरिकों को एक ही मंच पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार, आयुष) श्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. एम. श्रीनिवास, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा, मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, उत्तरप्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव एवं आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. सुनील कुमार बर्नवाल सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश को पीएम-केयर्स के तहत आधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरणों की सौगात

मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। इसके तहत आगामी तीन वर्षों में पीएम-केयर्स के माध्यम से प्रदेश को 13 एमआरआई मशीनें, 11 मैमोग्राफी मशीनें तथा 308 एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य एवं निदान (डायग्नोस्टिक) सेवाओं को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम-केयर्स के माध्यम से उपलब्ध होने वाले अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देंगे तथा विशेष रूप से दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

लोन का झांसा देकर सवा लाख ठगे

इंदौर। फाइनेंस कंपनी का अधिकारी बनकर एक ठग ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र से करीब सवा लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, वेरिफिकेशन और अन्य चार्ज के नाम पर किस्तों में रकम वसूली। बाणगंगा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। अनिरुद्ध भदौरिया ने पुलिस को बताया कि 18 जून को फेसबुक पर लोन से जुड़ा एक विज्ञापन दिखाई दिया। व्हाट्सएप पर संपर्क कर ठग ने दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी और फोटो मंगवाए। दस्तावेज मिलने के बाद एक लाख रुपए का लोन स्वीकृत होने का संदेश और स्वीकृति पत्र भेजा गया, जिस पर इंडियाबुल्स धानी फाइनेंस कंपनी का नाम अंकित था। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस के रूप में 2,250 रुपए यूपीआई से जमा कराए गए। अगले दिन 19 जून को आरोपी ने फिर संपर्क कर 10 मिनट में लोन राशि खाते में भेजने का भरोसा दिया और क्यूआर कोड भेजकर अतिरिक्त शुल्क जमा कराया। रकम नहीं आने पर रिफंड, जीएसटी, वेरिफिकेशन और अन्य प्रक्रिया का हवाला देकर अलग-अलग ट्रांजेक्शन कराए गए। बाद में लोन निरस्त कराने पर भी अतिरिक्त भुगतान मांगा गया। लोन नहीं मिलने पर छात्र को ठगी का अहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

भोपाल के छोटे तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत से हड़कंप

हवा में फैली बदबू, पानी में ऑक्सीजन की कमी होने की आशंका

भोपाल (नप्र)। राजधानी के ऐतिहासिक छोटे तालाब के किनारे रविवार को सैकड़ों की संख्या में मछलियां मृत पाई गईं। रविवार शाम को जब स्थानीय निवासी और सैर पर निकले लोग तालाब के किनारे पहुंचे, तो उन्हें पानी के घाटों पर मरी हुई मछलियों के ढेर दिखाई दिए। देखते ही देखते पूरे इलाके में भारी दुर्गंध फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत भोपाल नगर निगम के झील संरक्षण प्रकोष्ठ को मामले की जानकारी दी।

ऑक्सीजन की कमी या पानी में घुला जहर?– मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल नगर निगम के अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता ने देर शाम मौके का मुआयना किया और वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया। शुरुआती जांच और विशेषज्ञों के प्राथमिक अनुमान के मुताबिक, तालाब के पानी में अचानक 'घुलनशील ऑक्सीजन' का स्तर गिरने के कारण यह हादसा हुआ हो सकता है। हालांकि, अधिकारी पानी में किसी जहरीले प्रदूषक तत्व या केमिकल के मिलने की आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि ठीक सात साल पहले भी छोटे तालाब में इसी तरह बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत दर्ज की गई थी, जिससे इस घटना की गंभीरता और बढ़ जाती है।

शुरुआती वैज्ञानिक अनुमानों में पानी के भीतर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की भारी कमी को वजह माना जा रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम सोमवार को पानी के सैंपल लेकर केमिकल टेस्ट करेगी। लेक कंजर्वेशन सेल सोमवार सुबह से ही मृत मछलियों को हटाने और तट की सफाई के काम में जुट गया है।

छोटे तालाब में हुई मछलियों की इस सामूहिक मौत ने राजधानी के पर्यावरणविदों को चिंता में डाल दिया है। सात साल पहले हुई ऐसी ही घटना के बाद तालाब की सुरक्षा और वाटर ट्रीटमेंट को लेकर कई वादे किए गए थे, लेकिन इस घटना ने नगर निगम की तैयारियों पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

3 साल की जुड़वां बहनों ने रचा इतिहास

बनीं दुनिया की सबसे कम उम्र की फीमेल ड्रमर, लंदन में मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सम्मान

भोपाल (नप्र)। जिस उम्र में बच्चे ठीक से पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, उस उम्र में भोपाल की जुड़वां बहनें सान्वी नाहर और समन्वी नाहर ड्रम सेट पर अपनी थाप से विश्व रिकॉर्ड बना रही हैं।

महज 3 वर्ष 9 माह की उम्र में दोनों बहनों ने 'यंगेस्ट फीमेल ड्रमर' का खिताब हासिल कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन (यूके) में अपना नाम दर्ज कराया है।इस उपलब्धि के लिए दोनों को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमंस में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया।

सान्वी और समन्वी ने 21 मार्च 2026 को ड्रम सेट पर एक निर्धारित ट्रैक को 1 मिनट 20 सेकंड में सफलतापूर्वक पूरा कर यह रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड बनने के बाद संस्था ने उन्हें प्रमाण-पत्र, मेडल और ट्रॉफी प्रदान की। उनकी उपलब्धि को संस्था के आधिकारिक प्रकाशनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दर्ज किया गया है।

ड्रमिंग बेहद जटिल वाद्य यंत्र– बच्चियों की मां डॉ. निकिता नाहर ने बताया कि ड्रमिंग बेहद जटिल वाद्य यंत्र है, जिसे सामान्यतः पांच वर्ष की आयु के बाद ही सिखाया जाता है। लेकिन सान्वी और समन्वी ने महज सवा तीन साल की उम्र से ड्रम सीखना शुरू किया और नियमित अभ्यास के दम पर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चियों ने 1 मिनट 20 सेकंड तक लगातार ड्रम पर प्रस्तुति देकर

'यंगेस्ट फीमेल ड्रमर' का विश्व रिकॉर्ड बनाया।

डॉ. नाहर ने बताया कि यह पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है कि उनकी बेटियों को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमंस में आयोजित समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा सम्मानित किया गया। उनका मानना है कि बच्चों की रुचि को सही समय पर पहचानकर उचित मार्गदर्शन और निरंतर प्रोत्साहन दिया जाए तो वे छोटी उम्र में भी असंभव लगने वाली उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

सबसे कठिन विधाओं में माना जाता है– ड्रमिंग को संगीत की सबसे कठिन विधाओं में माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों हाथों और दोनों पैरों का एक साथ सटीक तालमेल जरूरी होता है।यही वजह है कि आमतौर पर बच्चों को पांच वर्ष की उम्र के बाद ही ड्रम सीखने की सलाह दी जाती है। लेकिन सान्वी और समन्वी ने महज सवा तीन साल की उम्र में ड्रम सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में ऐसा कौशल विकसित किया कि विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

कई शिक्षकों ने किया इनकार, एक गुरु ने स्वीकार की चुनौती– बच्चियों के माता-पिता उन्हें ड्रम सिखाने के लिए कई संगीत शिक्षकों के पास पहुंचे, लेकिन लगभग सभी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इतनी छोटी उम्र में ड्रम सीखना संभव नहीं है। ऐसे में भोपाल की योगी म्यूजिक वैली एकेडमी के ड्रम प्रशिक्षक युग (योग) नामदेव 'योगी' ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया।

उन्होंने बच्चियों को बिल्कुल शुरुआती स्तर से प्रशिक्षण देना शुरू किया। दो महीने में दोनों ने ड्रम की मूल बीट्स पर पकड़ बना ली। इसके बाद एक स्कूल कार्यक्रम में उनकी प्रस्तुति ने सभी को चौंका दिया। यहीं से उनके प्रदर्शन का वीडियो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक पहुंचा और रिकॉर्ड की प्रक्रिया शुरू हुई।

6सौ कर्मचारियों ने 200 एकड़ जंगल से हटाया अतिक्रमण

खंडवा में 30 जेसीबी लेकर पहुंचे थे, कल माफिया के हमले में 8 वनकर्मी हुए थे घायल

खंडवा (नप्र)। खंडवा में सोमवार को आमाखुजरी जंगल की करीब 200 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमणकारियों ने यहां पेड़-झाड़ियां काटकर मक्के की फसल बोई थी। वन, राजस्व और पुलिस विभाग के 600 अधिकारी-कर्मचारी 30 जेसीबी मशीनों के साथ कार्रवाई में जुटे, जो करीब 6 घंटे तक चली।

किसी भी तरह के विरोध से निपटने के लिए 60 महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहीं। टीम अपने साथ आंसू गैस लेकर पहुंची थी। जंगल में गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर झटका लगने से गैस का गोला फट गया। इसकी चपेट में कुछ पुलिसकर्मी आ गए। बाद में पेटी को खोलकर पूरी गैस बाहर की गई।

इस दौरान कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, एसपी अगम जैन, एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेकर और डीएफओ राकेश कुमार डामोर भी आमाखुजरी में रहे। इससे पहले रविवार को जंगल में बुआई रोकने गए 40 वनरक्षकों की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया था। इसमें 8 कर्मचारी घायल हो गए थे।

महिलाओं को आगे कर वन अमले पर बरसाए थे पत्थर– रविवार को आमाखुजरी जंगल में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर करीब 400 अतिक्रमणकारियों ने महिलाओं को आगे कर गोफन से पत्थर फेंके। लाठियों से भी हमला किया। किसी वनकर्मी का सिर फूट गया तो किसी का कान कट गया। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जल संरक्षण के संस्कार को संजोता मध्यप्रदेश

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

जल गंगा संवर्धन अभियान

(19 मार्च से 30 जून 2026)

समापन समारोह

हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्रामसभा
उत्कृष्ट योगदान देने वालों का सम्मान

मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन
नई जल संरचनाओं का लोकार्पण

मुख्य अतिथि

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

30 जून, 2026
भैंसवामाता, विकासखण्ड सारंगपुर, जिला राजगढ़

सरकार और समाज के परस्पर सहयोग की मिसाल

₹10,514 करोड़ लागत के जल संरक्षण एवं संवर्धन के 3.62 लाख कार्य पूर्ण

ग्रामीण क्षेत्र

- ₹1500 करोड़ की लागत से 66,483 खेत -तालाब बनकर तैयार
- 96,992 कूप रीचार्ज संरचनाओं का निर्माण, भू-जल संवर्धन को गति
- 216 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण
- बूंद-बूंद का सुनिश्चित उपयोग, 14,882 सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्रों का विस्तार
- ₹2253 करोड़ के 44,854 अन्य जल संरक्षण कार्य पूर्ण
- 800 से अधिक तालाबों के पाल एवं पिचिंग आदि की मरम्मत, सिंचाई की निर्बाध पहुंच
- 3,832 कि.मी. नहर प्रणालियों की सफाई एवं सिंचाई तंत्र को मजबूती
- 10,000 से अधिक कुएं, नदी एवं बावड़ियों की जनभागीदारी से सफाई

शहरी क्षेत्र

- 3100 से अधिक जल संरचनाएं हुईं अतिक्रमण मुक्त
- 9,400 से अधिक नालों की सफाई एवं सौंदर्यीकरण
- शासकीय एवं आवासीय भवनों में 35,500 से अधिक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणालियां स्थापित

अन्य क्षेत्र

- WOW Application के माध्यम से सभी स्कूलों के जल भंडारण टंकियों की सफाई
- स्कूल एवं आंगनवाड़ी में 1.60 लाख+ पेयजल सोतों का परीक्षण
- 6,000 से अधिक पाइप लाइनों में लीकेज सुधार कार्य पूर्ण
- 854 औद्योगिक इकाइयों में स्थापित हुई रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली
- बेतवा, शिप्रा, कान्ह एवं अन्य प्रमुख नदियों के जल का गुणवत्ता परीक्षण एवं नालों का चिह्नांकन

वन क्षेत्र

- 1.30 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य पूर्ण

D-11048/26

सीधा प्रसारण @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP